EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By – Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 03/12/2025

पांच दिनों में दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं अंशु

अंशु जामसेनपा का जन्म 1979 में आज ही अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। 2003 में पति के यात्रा व्यवसाय में जुड़ गईं और हिमालय के आसपास ट्रेकिंग और नदी पार करने के अभियानों पर ग्राहकों को ले जाना शुरू किया। इसी दौरान पर्वतारोहण में उनकी रुचि जगी और उन्होंने गहन प्रशिक्षण लेना शुरू किया। पहली बार 16 मई, 2017 को सुबह 9 .15 बजे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचीं। बेसकैंप लौटने के पांच दिन बाद इस उपलब्धि को दोहराते हुए 21 मई को सुबह 7 .45 बजे फिर शिखर पर पहुंच गईं और पांच दिनों में दो बार एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गईं।

फीनिक्स और लाइन द्वीप समूह में नहीं आई 31 दिसंबर की तिथि

1994 में किरिबाती के फीनिक्स व लाइन द्वीप समूह में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व की ओर खिसकाए जाने के कारण 31 दिसंबर की तिथि नहीं आई थी। 30 दिसंबर के बाद सीधे एक जनवरी आ गया, ताकि पूरे देश में एक ही तारीख का पालन हो सके।

बोल्टन जूनियर ने पहली इलेक्ट्रिक साइकिल का पेटेंट कराया

1895 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक ओग्डेन बोल्टन जूनियर ने पहली ज्ञात इलेक्ट्रिक साइकिल का पेटेंट प्राप्त किया था। इसके पीछे के पहिये में एक हब मोटर लगा था, जो आधुनिक ई-बाइक्स की अवधारणा के समान था। इसमें पैडल नहीं थे।

DAINIK JAGARAN PAGE NO- 18

एटमी कार्यक्रम पर ईरान को चेताया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन्हें कुचलना पड़ेगा

कड़ा संदेश

पाम बीच (फ्लोरिडा), एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फ्लोरिडा स्थित अपने आवास 'मार-ए-लागो' में स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा।

नेतन्याहू के पहुंचने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें खबर मिल रही है कि ईरान फिर से अपने परमाणु ढांचे को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा, अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन्हें कुचलना पड़ेगा। हम उन्हें पूरी तरह हरा देंगे। हालांकि, हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो रहा है।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि जून में ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहीं, इजराइली मीडिया में कहा गया है ईरान इजराइल पर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलें फिर से तैयार कर सकता है। ईरान का कहना है वह देश के किसी भी हिस्से में यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है और वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, माना जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह मुलाकात गाजा संकट के लिहाज से भी अहम है।

पाम बीच में अपने आवास पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत करते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। • एएफपी

ट्रंप ने भारत-पाक जंग रुकवाने का फिर दावा किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के दौरे पर अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत-पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाने के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को टैरिफ की धमकी देकर रोका, खुद ही अन्य संघर्षों को भी, लेकिन इसके लिए उन्हें श्रेय नहीं दिया जाता। इसके बाद उन्होंने अपने दावे को दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बंद करवा दी। गौरतलब है कि इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत-पाक संघर्ष रुकवाने का दावा कर चुके हैं।

HINDUSTAN PAGE NO – 21 & 22

अंतरिक्ष से लौटे चूहे ने नौ बच्चे जन्मे

बीजिंग, एजेंसी। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से जीवित लौटे चूहे ने पृथ्वी पर बच्चे को जन्म दिया।

हाल ही में चीन ने चार चूहों को मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा था। ये चूहे वहां करीब दो हफ्ते रहे और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। पृथ्वी पर लौटने के बाद एक मादा

■ चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर चार चूहों को हाल ही में भेजा था

गर्भवती हुई और उसने नौ चूहों को जन्म दिया। इनमें से छह बच्चे जीवित और स्वस्थ हैं। यह चूहों में सामान्य जीवित रहने की दर मानी जाती है। मां बच्चों को सामान्य रूप से दूध पिला रही है। अब भविष्य में चांद और मंगल मिशन के लिए लंबे अंतरिक्ष सफर में इंसानों की सेहत और प्रजनन को समझने में मदद मिलेगी। चूहों का बच्चे पैदा करना दिखाता है कि जीवन अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है।

केएलएफ 2026 में शामिल होंगी सुनीता

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स केरल लिटरेचर फेस्टिवल (केएलएफ) 2026 में हिस्सा लेंगी। यह महोत्सव 22 जनवरी से शुरू होगा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 300 से अधिक दिन बिता चुकी हैं।

इस महोत्सव में सुनीता अपनी अंतरिक्ष यात्राओं के अनुभव साझा करेंगी और विज्ञान, खोज, नेतृत्व, साहस, धैर्य और मानव जिज्ञासा जैसे विषयों पर विचार रखेंगी।

क्या आप जानते हैं

आज के ही दिन अमेरिका में खुला था पहला बैंक

1781 में 31 दिसंबर को अमेरिका में पहला बैंक खुला था और इसे आधिकारिक मान्यता मिली थी

- बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाम का यह बैंक अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर में था
- यह बैंक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए बनाया गया था
- यह अमेरिका का पहला आधिकारिक चार्टर्ड बैंक था और इससे पहले 'कैंटीय बैंक' के रूप में कार्य किया
- हालांकि बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका अब अपने मूल नाम और रूप में अब सक्रिय नहीं है
- यह बैंक 18वीं-19वीं सदी में काम करता रहा और बाद में कई कारणों से दूसरे बैंकों में विलय होता गया
- इसने अपने खुद के बैंक नोट जारी किए, जिन्हें लोग सोने या चांदी के बदले भुना सकते थे। इससे लोगों का मुद्रा पर भरोसा बढ़ा

पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन के साथ हमला

यूक्रेन ने इनकार किया, कहा- झूठ बोल रहा रूस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

रूस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में झील किनारे स्थित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रूस की ओर से चेतावनी दी गई है कि हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा।

व्लादिमीर पुतिन

इससे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे शांति के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की ओर से आरोप से पूरी तरह इनकार करते हुए कहा गया है कि यह शांति वार्ता को बेटपरी करने का रूस का बहाना है। रूस झूठ बोल रहा है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के आवास पर हमले पर चिंता जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जारी कूटनीतिक कोशिशें संघर्ष खत्म करने और शांति कायम करने का सबसे बेहतर रास्ता है। सभी पक्ष ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचे।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अनुसार यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की दरम्यानी रात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के झील किनारे स्थित आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दी कि हमले का जवाब दिया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोप-प्रत्यारोप के बीच कहा है कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के पहले से कहीं अधिक करीब हैं, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ बाधाएं अभी भी समझौते में रुकावट डाल सकती हैं।

JANSATTA PAGE NO- 1

कैमूर टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा

पटना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

विभाग की ओर से तैयार किए गए संशोधित प्रस्ताव को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) भेजने पर विभागीय मंत्री डॉ. प्रेम कुमार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही केंद्र सरकार को यह संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा।

विभाग के पदाधिकारी ने मंगलवार को बताया कि कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो कैमूर पर्वत शृंखला में फैला हुआ है। यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।

HINDUSTAN PAGE NO- 2

अर्थशास्त्रियों ने निवेश बढ़ाने के सुझाव दिए, प्रधानमंत्री ने कहा

आर्थिक वृद्धि के लिए सतत सुधार जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नीति आयोग में जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की और इस संवाद के दौरान उनके विचार जाने।

प्रधानमंत्री ने जहां वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने और सतत आर्थिक सुधार जारी रखने पर जोर दिया, वहीं आर्थिक विशेषज्ञों ने निजी निवेश बढ़ाने, विदेशी निवेश प्रवाह को तेज करने और नीतिगत व मौद्रिक सुधारों को अपनाने का सुझाव दिया। इस संवाद का विषय 'आत्मनिर्भरता एवं संरचनात्मक रूपांतरण: विकसित भारत के

बाकी पेज 8 पर

दिल्ली में बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

JANSATTA PAGE NO- 1

बरेली में जन्मदिन कार्यक्रम में खलल डाले जाने के बाद छात्रा ने कहा | **सवाल** | मुझे काफी शर्मिंदगी है कि मेरे मित्रों को परेशान किया गया

क्या मुझे अपने दोस्तों का चुनाव धर्म के आधार पर करना चाहिए?

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

बरेली के एक कैफे में शनिवार को जन्मदिन के जश्न में कुछ उपद्रवियों द्वारा व्यवधान किए जाने और लव जिहाद के आरोप लगाए जाने के तीन दिन बाद 22 वर्षीय छात्रा ने कहा कि इस घटना ने उसे व्यथित कर दिया है। छात्रा ने कहा कि क्या अब मुझे दोस्तों का चुनाव उनके धर्म के आधार पर करना होगा?

अंतिम वर्ष की नर्सिंग छात्रा ने कहा कि मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरे दोस्तों को परेशान किया गया और उन पर हमला किया गया। मैं डर के मारे घर में ही बंद हूं और बाहर कदम नहीं रख रही हूं। 27 दिसंबर को 24 उपद्रवी कैफे में घुस गए और जन्मदिन मनाने वाले समूह और कर्मचारियों पर हमला किया। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बताया जाता है कि यह घटना पार्टी में मुसलिम समुदाय के दो युवकों की उपस्थिति के कारण हुई। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल नहीं हैं। हालांकि ऋषभ और दीपक के बजरंग दल से संबंध होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन संगठन के बरेली समन्वयक आर्यन चौधरी ने इस दावे का खंडन किया।

> *छात्रा* ने बताया, 'हंगामे के बाद वह अपने संस्थान में वापस नहीं लौटी है और छात्रावास छोड़ दिया है। मैं अवसाद से गुजर रही हूं। इसने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश और उससे भी आगे मेरी छवि को धूमिल कर दिया है।'

पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में शान और वकीब नाम के दो युवकों और कैफे मालिक शैलेंद्र गंगवार को हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने बताया था कि बाद में उन्हें निजी मुचलकों पर जमानत दे दी गई थी। बदायूं जिले की रहने वाली यह छात्रा पिछले चार वर्षों से नर्सिंग संस्थान के छात्रावास में रह रही है। उसके पिता किसान हैं और वह दो भाई-बहनों में सबसे बड़ी है। बरेली में अपनी मौसी के घर पर रह रही उसने 27 दिसंबर को घटी घटना का ब्योरा दिया। उसने कहा, 'मैंने अपने 40 सहपाठियों को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल 12 ही आ सके। उनमें वकीब और शान भी शामिल थे।' उसने दावा किया कि दोपहर करीब 12:30 बजे उसके दोस्त कैफे में इकट्ठा हुए। लगभग एक घंटे बाद जब वह अपना जन्मदिन का केक काट रही थी, तभी हमलावरों का एक समूह नारे लगाते हुए अंदर घुस आया। उन्होंने मेरे सहपाठियों, वकीब और शान पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे धर्म के बारे में पूछताछ करते हुए मेरे सहित अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया।

छात्रा ने कहा कि मेरे दोस्तों ने उनसे हमें जाने देने की गुहार लगाई। हालांकि उन्हें हाल से बाहर धकेल दिया गया। हमलावरों ने वकीब और शान को पीटना जारी रखा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उसने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसका मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की। उसने बताया कि हंगामे के बाद वह अपने संस्थान में वापस नहीं लौटी है और छात्रावास छोड़ दिया है। मैं अवसाद से गुजर रही हूं क्योंकि इसने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे देश के आगे मेरी छवि को धूमिल कर दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि इन हमलावरों को लोगों का न्याय करने और यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए।

उसने कहा कि उसके माता-पिता और रिश्तेदारों ने कभी भी उसके मुसलिम दोस्तों से कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें पोस्ट करती हूं- मैंने जन्मदिन का जश्न अपने माता-पिता से पूछने के बाद ही आयोजित किया। वे जानते हैं कि मेरे दोस्त कौन हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो ये लोग मुझे मार्गदर्शन देने वाले कौन होते हैं? उन्होंने आगे कहा कि न तो उनकी परवरिश और न ही उनका पेशा उन्हें धर्म के आधार पर लोगों को आंकने या उनमें भेदभाव करने की शिक्षा देता है। छात्रा ने आगे आरोप लगाया कि हमला सुनियोजित प्रतीत होता है।

JANSATTA PAGE NO- 1

केंद्र सरकार ने कहा

जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

> *वित्त* वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 8.2 फीसद रही। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 7.8 फीसद और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4 फीसद से अधिक है। एक सरकारी बयान के अनुसार कि भारत ने 4,180 अरब अमेरिकी डालर के मूल्यांकन के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया और अनुमान है कि 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डालर की जीडीपी के साथ जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने की स्थिति में है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है।

भारत 4,180 अरब अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक जर्मनी को पीछे करके तीसरे स्थान पर पहुंचने की स्थिति में है। एक सरकारी बयान में यह कहा गया। भारत लगातार मजबूत वृद्धि आंकड़ों के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 8.2 फीसद रही। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 7.8 फीसद और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4 फीसद से अधिक है। एक सरकारी बयान के अनुसार कि भारत ने 4,180 अरब अमेरिकी डालर के मूल्यांकन के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया और अनुमान है कि 2030 तक 7,300 अरब अमेरिकी डालर की जीडीपी के साथ जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने की स्थिति में है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। बयान में कहा गया कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि छह तिमाहियों के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो वैश्विक व्यापार में बनी अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की मजबूती को दर्शाती है। मजबूत निजी उपभोग जैसे घरेलू कारकों ने इस विस्तार को सहारा देने में प्रमुख भूमिका निभाई। बयान में विभिन्न संस्थानों के अनुमानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय एजंसियों ने इसकी पुष्टि की है। विश्व बैंक ने 2026 में 6.5 फीसद की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

वहीं, मूडीज का अनुमान है कि भारत 2026 में 6.4 फीसद और 2027 में 6.5 फीसद की वृद्धि के साथ जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.6 फीसद और 2026 के लिए 6.2 फीसद कर दिया है।

JANSATTA PAGE NO- 10

जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी इकोनमी बना भारत

- अगले ढाई से तीन वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत
- मजबूत निजी खपत के नेतृत्व में घरेलू कारकों ने जीडीपी विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाई

नई दिल्ली, ब्यूरो: वर्ष 2025 में 4.18 ट्रिलियन डालर की जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनमी बन गया है और ढाई-तीन वर्षों में यह जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। सरकार की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

सरकार ने विशेषज्ञों के हवाले से यह भी अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी का आकार 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डालर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में विकास दर छह तिमाहियों में सबसे ज्यादा रही है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन दूसरे स्थान पर है।

2025 में सुधारों की एक झलक देने वाले एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मजबूत निजी खपत के नेतृत्व में घरेलू कारकों ने जीडीपी विस्तार में केंद्रीय भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने इस बात को दोहराया है कि भारत की विकास दर आगे भी तेज होगी। मूडीज को उम्मीद है कि भारत 2026 में 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.5 प्रतिशत की दर के साथ जी20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी होगी। आइएमएफ ने 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.2 प्रतिशत कर दिया है। ओईसीडी ने 2025 में 6.7 प्रतिशत और 2026 में 6.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है।

सरकार ने कहा, 'भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनमी में से एक है और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। 2047 तक (आजादी के सौ साल पूरे होने तक) हाई मिडिल इनकम वाला देश बनने के सपने के साथ देश विकास दर और ढांचागत सुधारों को मजबूत करने पर काम कर रहा है।'

पूरे साल महंगाई में की नरमी: सरकार ने कहा-पूरे साल महंगाई का ट्रेंड काफी हद तक ठीक रहा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित महंगाई दर जनवरी के 4.26 प्रतिशत से लगातार कम होकर नवंबर में 0.71 प्रतिशत हो गई। थोक मुद्रास्फीति भी साल के दौरान कम हुई, जिससे कीमतों में स्थिरता का माहौल मजबूत हुआ।

तीसरी सबसे बड़ी इकोनमी बनने से यह होगा बदलाव

- आगे अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनमी होगा
- वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा
- सैन्य क्षमता के लिहाज से भारत की ताकत में बढ़ोतरी होगी
- बड़ी इकोनमी का मतलब है जन कल्याण के लिए ज्यादा संसाधन
- संसाधनों की उपलब्धता से देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा
- लोगों की प्रति व्यक्ति आय में तेजी से इजाफा होगा

रोजगार के मोर्चे पर हुआ सुधार

रोजगार की स्थिति में भी सुधार दिखा है। नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर अक्टूबर के 5.2 प्रतिशत से घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल 2025 के बाद सबसे कम दर्ज किया गया स्तर है। यह गिरावट बड़े पैमाने पर थी। सुधार में शहरी और ग्रामीण दोनों ने योगदान दिया।

DAINIK JAGARAN PAGE NO- 1

एआइ एजेंट बने हकीकत, 2026 में चुनौतियां बरकरार

जनसत्ता विशेष

तकनीक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में 2025 एक निर्णायक मोड़ के रूप में उभरा, जब शोध प्रयोगशालाओं और प्रोटोटाइप तक सीमित प्रणालियां रोजमर्रा के औजारों के तौर पर सामने आने लगीं। इस बदलाव के केंद्र में एआइ एजेंटों का उदय रहा। ऐसी एआइ प्रणालियां जो अन्य साफ्टवेयर टूल का उपयोग कर सकती हैं और स्वायत्त रूप से काम कर सकती हैं। हालांकि एआइ पर 60 से अधिक वर्षों से शोध हो रहा है और 'एजेंट' शब्द लंबे समय से प्रचलन में है, लेकिन 2025 यह साल रहा जब यह अवधारणा डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के लिए ठोस रूप में सामने आई।

एआइ एजेंट सिद्धांत से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे का हिस्सा बने और बड़े भाषा माडल्स के साथ लोगों की बातचीत का तरीका बदल दिया, जो चैटजीपीटी जैसे चैटबाट्स को शक्ति देते हैं। 2025 में एआइ एजेंट की परिभाषा में भी बदलाव आया। अकादमिक दृष्टि से 'देखने, सोचने और कार्रवाई करने' वाली प्रणालियों से हटकर, एआइ कंपनी एंथ्रापिक ने इसे ऐसे बड़े भाषा माडल के रूप में परिभाषित किया जो साफ्टवेयर टूल का उपयोग कर सकें और स्वायत्त कार्रवाई कर सकें। हालिया बदलाव इन माडलों की 'एक्शन क्षमता' का विस्तार है। टूल्स का इस्तेमाल एपीआइ काल करना, अन्य प्रणालियों से समन्वय और स्वतंत्र रूप से कार्य पूरे करना। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। 2024 के अंत में एंथ्रापिक द्वारा माडल कान्टेक्स्ट प्रोटोकाल जारी किया गया, जिसने डेवलपर को बड़े भाषा माडलों को बाहरी टूल्स से मानकीकृत तरीके से जोड़ने की सुविधा दी। इसके साथ ही 2025 को एआइ एजेंटों का वर्ष बनने का आधार तैयार हुआ।

JANSATTA PAGE NO- 7

अमेरिका के बाद चीन ने भारत-पाक तनाव में मध्यस्थता का किया दावा

भारत लगातार यह कहता रहा है कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है

बैजिंग, 30 दिसंबर (भाषा)।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को दावा किया कि इस वर्ष चीन द्वारा 'मध्यस्थता' किए गए प्रमुख संवेदनशील मुद्दों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल रहे। भारत का यह कहना रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सात से 10 मई के दौरान संघर्ष का समाधान दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से हुआ था। भारत लगातार यह कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान से संबंधित मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है।

बेजिंग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग ने कहा कि इस साल, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के। भू-राजनीतिक उथल-पुथल लगातार फैलती जा रही है।

फिल्म 'बैटल आफ गलवान' की आलोचना

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा)।

सलमान खान अभिनीत फिल्म 'बैटल आफ गलवान' का 1.12 मिनट का टीजर जारी होने के बाद चीनी मीडिया में हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने कहा कि सिनेमा कलात्मक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और भारत इसे प्रतिबंधित नहीं करता है। यह फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है।

चीन के मीडिया संस्थान 'ग्लोबल टाइम्स' ने इस फिल्म को सिनेमाई अतिशयोक्ति बताया और दावा किया कि इसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान ने बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाई है। साल 2020 में भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए बाबू और 16 बिहार रेजिमेंट के 19 अन्य सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।

उन्होंने कहा कि स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, हमने एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत रुख अपनाया है, और लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

JANSATTA PAGE NO- 12

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया नहीं रहीं | दु:खद | आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक

उतार-चढ़ाव से भरा रहा खालिदा का राजनीतिक सफर

ढाका, 30 दिसंबर (एपी)।

खालिदा जिया ने बांग्लादेश में सैन्य तानाशाह के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ कर 1990 में तत्कालीन तानाशाह और पूर्व सेना प्रमुख एचएम इरशाद का पतन करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका राजनीतिक जीवन उतार- चढ़ाव से भरा रहा। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन पर दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों को उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था।

जनवरी 2025 में उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ अंतिम भ्रष्टाचार मामले में उन्हें बरी कर दिया था, जिससे फरवरी में होने वाले आम चुनाव में उनके उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ हो गया था। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए बांग्लादेश के शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और तख्तापलट जैसे घटनाक्रम देखने को मिले। जिया के पति जियाउर रहमान ने 1977 में सेना प्रमुख के रूप में सत्ता संभाली और 1978 में बीएनपी की स्थापना की। 1981 में एक सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद खालिदा जिया ने सैन्य तानाशाही के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप 1990 में तत्कालीन तानाशाह और पूर्व सेना प्रमुख एच एम इरशाद का पतन हुआ।

खालिदा जिया ने 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला। उन चुनावों में और इसके बाद कई चुनावों में उनकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना रहीं, जो मुक्ति संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री थीं। 1996 के शुरुआती चुनाव में व्यापक बहिष्कार के बीच बीएनपी ने 300 में से 278 सीटें जीतीं, लेकिन कार्यवाहक सरकार की मांग के चलते जिया सरकार केवल 12 दिन ही चल सकी। उसी वर्ष जून में नए चुनाव कराए गए। जिया 2001 में फिर सत्ता में लौटीं और इस दौरान उनकी सरकार में जमात-ए-इस्लामी भी शामिल थी।

उनके दूसरे कार्यकाल (2001-06) में भारत-विरोधी बयानबाजी और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को लेकर आरोप लगे। इसी अवधि में उनके बड़े बेटे तारिक रहमान पर सत्तानांतर सत्ता चलाने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2004 में ढाका में हुए ग्रेनेड हमले के लिए शेख हसीना ने जिया सरकार और रहमान को जिम्मेदार ठहराया था। जिया को भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों में 17 साल की सजा सुनाई गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिया के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का मसविदा जारी | पहल | मांगे गए थे सुझाव

कृत्रिम मेधा व नवाचार में संवारा जाएगा युवा कौशल

हिमांशु अग्निहोत्री
नई दिल्ली, 30 दिसंबर।

देश के युवा अब शारीरिक खेलों से लेकर डिजिटल दुनिया के हर क्षेत्र में चमकने को तैयार हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2025 (एनवाईपी-2025) के मसविदा में खेलकूद और मनोरंजन को युवाओं के समग्र विकास का मजबूत आधार बनाया गया है। नीति में कौशल विकास (जैसे कृत्रिम मेधा, डेटा विश्लेषण), खेल, डिजिटल जुड़ाव, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना है, जिसके लिए सुझाव मांगे गए थे। इस सुझाव में लगभग 400 लोगों ने अपने विचार साझा किए, जिसे अब विभाग इन विचारों पर परामर्श करेगा।

खेल के क्षेत्र में एनवाईपी-2025 को हाल ही में मंजूर हुई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 से जोड़ा जाएगा। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, प्रतिभा की जल्दी पहचान होगी और युवा महिलाओं, ग्रामीण युवाओं तथा दिव्यांगजन के लिए विशेष पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सामुदायिक खेल क्लब और युवा केंद्रों के जरिए गांव की लड़कियां और दिव्यांग युवा भी मैदान में उतर सकेंगे।

नीति का मकसद युवाओं को भविष्य की नौकरियों (जैसे कृत्रिम मेधा, हरित ऊर्जा) के लिए तैयार करना है। शारीरिक शिक्षा, प्रतिभा पहचान और ग्रामीण व दिव्यांग युवाओं के लिए खेल सुविधाओं में सुधार के लिए युवाओं को तैयार करना। मीडिया साक्षरता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मंच पर रचनात्मकता को बढ़ावा देना। युवाओं को उद्यमशीलता और रचनात्मकता के लिए प्रेरित करना। सामाजिक मुद्दों को सुलझाने और सामुदायिक विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

खेल के क्षेत्र में एनवाईपी-2025 को हाल ही में मंजूर हुई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 से जोड़ा जाएगा। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, प्रतिभा की जल्दी पहचान होगी और युवा महिलाओं, ग्रामीण युवाओं तथा दिव्यांगजन के लिए विशेष पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सामुदायिक खेल क्लब व युवा केंद्रों के जरिए गांव की लड़कियां और दिव्यांग युवा भी मैदान में उतर सकेंगे। डिजिटल मनोरंजन के युग में ये नीति रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। युवाओं को डिजिटल कौशल, रचनात्मक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता के अवसर मिलेंगे, ताकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या पाडकास्ट से वे कमाई कर सकें। साथ ही, मीडिया साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर जोर होगा, ताकि आनलाइन दुनिया में वे सुरक्षित रहें।

दस हजारी की अगली कड़ी में राशि की मात्रा काम-धंधे के आधार पर

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : दस हजारी योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि वर्ष 2025 के साथ ही समाप्त हो रही है। बहरहाल जीविका के अधिकारियों का आकलन है कि योजना का लाभ पाने वाली महिलाएं लगभग दो करोड़ के आसपास होंगी। अब अगली कड़ी में लाभार्थियों द्वारा किए जा रहे रोजगार का मूल्यांकन होगा, जिसके निमित्त यह राशि वितरित हो रही है। जिन महिलाओं के काम-धंधे को आगे बढ़ाने योग्य पाया जाएगा, उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2.10 लाख रुपये देने की घोषणा किए हैं, लेकिन पात्र सभी महिलाओं को इतनी ही मात्रा में राशि नहीं मिलने वाली। उनके काम के मूल्यांकन के आधार पर देय राशि का निर्धारण जीविका द्वारा किया जाएगा। अलबत्ता यह राशि अधिकतम 2.10 लाख रुपये तक होगी। योजना के अंतर्गत आवेदकों की संख्या बढ़कर 1.90 करोड़ से अधिक हो गई है। इनमें से 1.44 करोड़ महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जिन्हें राशि का भुगतान हो चुका है। आवेदन के लिए 31 दिसंबर अंत तक अवधि विस्तार हुआ था। उसके बाद दिसंबर में ही 23 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन आवेदनों की छंटनी कर पात्र महिलाओं को यथाशीघ्र दस-दस हजार रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा, जिसे वापस नहीं करना है। हालांकि, काम-धंधे के विस्तार के लिए मिलने वाली राशि के साथ वापसी की शर्त भी होगी। दस हजारी के नाम से लोकप्रिय यह वस्तुतः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, जिसका क्रियान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। विस चुनाव से पहले इसकी घोषणा हुई थी। पहले ग्रामीण महिलाएं ही इसके लिए पात्र थीं। बाद में शहरी क्षेत्र को भी इस दायरे में लाया गया। शहरी क्षेत्र से 18 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। अभी तक किसी को भी पहली किस्त जारी नहीं हुई है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण दस-दस हजार रुपये उन 470 पुरुषों को भी हस्तांतरित हो गए हैं, जो दिव्यांग हैं। हालांकि, सरकार के स्तर से उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। वैसे भी उनके परिवारों की महिलाओं ने योजना के लाभ के लिए आवेदन किया है। पात्रता पूरी होने पर यह राशि सहजता से समायोजित हो जाएगी।

- अगली किस्त अधिकतम 2.10 लाख रुपये तक, सभी मामलों में एक समान भुगतान नहीं
- दिव्यांग पुरुषों को हुए भुगतान के विरुद्ध नहीं होगी कार्रवाई, राशि समायोजन की संभावना

2 करोड़ महिलाएं हो सकती हैं दस हजारी की लाभार्थी, इनमें लगभग 18 लाख शहरी क्षेत्र से

बिहार में लगभग 2.7 करोड़ परिवार हैं

बिहार में लगभग 2.7 करोड़ परिवार हैं। उनमें से 21 लाख से कुछ अधिक करदाता हैं। इनके अलावा सरकारी सेवक व शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार भी हैं। इस हिसाब से जीविका का आकलन है कि लगभग दो लाख महिलाएं दस हजारी के लिए आवेदक हो सकती हैं। योजना का उद्देश्य इसके दूसरे पड़ाव से पूरा होना है, जब पहली किस्त से शुरू हुआ काम-धंधा रोजगार के रूप में परिवर्तित होने लगे। तब कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। जीविका की योग्यता व दक्षता की परख भी वहीं पर होनी है, क्योंकि तब फील्ड सर्वे भी करना होगा। स्पष्ट है कि योजना की अगली कड़ी में दी जाने वाली राशि कारोबार के दावे और सर्वेक्षण के आधार पर तय होगा। सभी मामलों में यह एक समान नहीं होगी, पर यह 2.10 लाख से अधिक भी नहीं होगी। इसके भुगतान व वापसी के लिए जीविका के स्तर पर अभी नियम बनाए जा रहे हैं।

जागरण विशेष

वैज्ञानिक सोच का साथ तो 'खुशबू' से महक उठे हजारों परिवार

सीएसआइआर की मदद से जम्मू-कश्मीर में छाई बैंगनी क्रांति, ग्रामीण आजीविका को मिली उड़ान

रोहित जंडियाल • जागरण

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह में किसानों के पसीने के साथ वैज्ञानिक सोच के मेल का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। इसकी खुशबू से यहां के हजारों परिवार महक रहे हैं।
लैवेंडर पुदीना परिवार की एक वनस्पति है। जिसका फूल बैंगनी कलर का होता है। इसमें सूजनरोधी और एंटी आक्सीडेंट के गुण होते हैं। इससे दवाईयां बनती हैं।
यहां एरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती किसानों के जीवन में ऐसी क्रांति लाई है कि इसकी महक पूरे देश में महसूस की जा रही है। भद्रवाह आज बैंगनी क्रांति के लिए देश की प्रेरणा बन गया है। इस क्रांति ने प्रदेश के चार हजार से अधिक किसान परिवारों का जीवन बदला है, साथ ही ग्राम विकास की नई राह भी खोली है।

किसानों के उत्साह, हौसले और मेहनत का परिणाम यह है कि औद्योगिक प्रशिक्षण के बाद वह केवल लैवेंडर के फूल ही नहीं उगा रहे पर उससे बने उत्पाद देश-विदेश तक पहुंचा रहे हैं। यह किसान अब प्रति एकड़ तीन से 20 लाख रुपये सालाना कमा रहे हैं। अकेले लैवेंडर के तेल की बिक्री से भद्रवाह के किसानों ने पांच वर्ष में दस करोड़ से अधिक की आय अर्जित की है। इसके अलावा साबुन, खुशबू, अगरबत्ती और अन्य उत्पाद बना दर्जनों युवा आजीविका चला रहे हैं। लैवेंडर की खुशबू पर्यटकों को भी लुभा रही है।

सीएसआइआर के विज्ञानियों के अनुसार दस वर्ष पूर्व तक यह किसान केवल मक्का और अन्य परंपरागत फसल तक ही सीमित थे। यह क्षेत्र लैवेंडर की खेती के लिए उपयुक्त है और सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' के तहत एरोमा मिशन के लिए चुना तो संस्थान के समक्ष बड़ा कार्य था।

किसानों को खेती के लिए राजी करना, उनका प्रशिक्षण और उसके बाद अगले चरण में उन्हें स्टार्टअप की राह तक ले जाने के लिए लंबी मेहनत लगी। प्रशिक्षण के साथ किसानों को लैवेंडर के पौधे उपलब्ध कराए गए। खेती के तरीके बताकर गांव के युवाओं को मशीनें उपलब्ध कराई गईं।

खेतों में लैवेंडर के फूल चुनती महिलाएं • जागरण

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला

सीएसआइआर के नेतृत्व वाले अरोमा मिशन को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (टीम पुरस्कार) प्रदान किया गया। यह सम्मान कृषि, ग्रामीण विकास और देश की अरोमा अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं तकनीकी योगदान के लिए दिया गया।

लैवेंडर के जरिए पर्यटन को भी मिल रहा बढ़ावा

लैवेंडर की महक से पर्यटकों को लुभाने के लिए लैवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत की गई। भद्रवाह में प्रतिवर्ष लैवेंडर महोत्सव हो रहा है और यहां काफी पर्यटकों की भागीदारी रहती है। एरोमा मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक सराहना मिली है।

एरोमा मिशन से जम्मू-कश्मीर के हजारों किसान जुड़े हैं। हमारे विज्ञानियों की टीम ने इस मिशन को किसानों की सहायता से धरातल पर सफल बनाया है। अभी तीन चरणों में इसे लागू किया गया है। इसके चौथे चरण का भी प्रस्ताव है। किसानों को एक ही मंच पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो उन्हें और लाभ होगा।

डा. जबीर अहमद, उपनिदेशक, सीएसआइआर-आइआइआइएम जम्मू

2015 में हुई शुरुआत: जम्मू-कश्मीर में एरोमा मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। अब इसका दायरा बढ़ा अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुल 1,625 हेक्टेयर क्षेत्र में लैवेंडर की खेती हो रही है। पहले चरण में भद्रवाह के 600 किसानों को शामिल कर 164.92 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती विकसित की गई।

दूसरे चरण में 910.71 हेक्टेयर में लैवेंडर खेती का विस्तार हुआ और करीब 2,100 नए किसान जुड़े। वर्तमान में चल रहे तीसरे चरण में 549.38 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 1,500 से अधिक किसानों को लाभ मिला है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकाप्टर में अब आम नागरिक करेंगे सफर

- मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन एवं आपदा राहत कार्यों के लिए भी होगा इस्तेमाल
- नई पीढ़ी के हेलीकाप्टर को उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

बेंगलुरु में मंगलवार को एचएएल में ध्रुव-एनजी हेलीकाप्टर की प्रथम उड़ान से पूर्व पूजा-अर्चना करते नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू। • एएनआइ

बेंगलुरु, प्रेट्र : अब तक सिर्फ सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने वाले ध्रुव हेलीकाप्टर में अब आम नागरिक भी सफर कर सकेंगे। इसका मकसद मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में हेलीकाप्टर सेवाओं को बढ़ाना है। हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा बनाए गए तथा कई भूमिकाओं को अंजाम देने वाले नई पीढ़ी के इस हेलीकाप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान को नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाई और इसे देश की क्षमता का प्रतीक बताया।

पहली उड़ान देखने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि यह घटना "भारतीय विमानन इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर" है और उन्होंने इस उपलब्धि के लिए डिजाइनरों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और एचएएल के पूरे वर्कफोर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एचएएल लंबे समय से एक ऐसे साइकिल की तरह काम कर रहा था जिसका एक पहिया यानी डिफेंस ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब यह एक बैलेंस्ड आर्गनाइजेशन बन रहा है जो दो बराबर पहियों - डिफेंस और सिविल एविएशन - पर चल रहा है। उन्होंने कहा, "नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर यह मेरे लिए खासकर गर्व का पल है।" यह घटनाक्रम स्वदेशी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भारत के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक उड्डयन बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए एचएएल द्वारा डिजाइन और निर्मित बहुउद्देशीय हेलीकाप्टर ध्रुव सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि यह भारत की काबिलियत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसे खास तौर पर वैश्विक नागरिक उड्डयन बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। उड्डयन क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती विकास यात्रा का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री के विजन की वजह से देश आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार बन गया है।

DAINIK JAGARAN PAGE NO- 18

पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के दिमाग में अधिक इम्यून रिस्पांस

अध्ययन ▶ उम्र से संबंधित विकार है अल्जाइमर, जिसमें उम्र के साथ बोलने, सोचने व याददाश्त घटती जाती है

अल्जाइमर रोग से ग्रस्त मादा चूहों के अध्ययन में पाया गया परिणाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : अल्जाइमर रोग से ग्रस्त मादा चूहों के मस्तिष्क में प्रतिरक्षा कोशिकाएं पुरुषों की तुलना में न्यूरोइन्फ्लेमेशन में शामिल जीनों की गतिविधि को अधिक सक्रिय करने की प्रवृत्ति रखती हैं। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है।

इसमें पाया गया कि ज्यादा महिलाओं में इस न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी का पता क्यों चलता है। अल्जाइमर रोग एक उम्र से संबंधित विकार है जिसमें उम्र के साथ बोलने, याददाश्त व सोचने की प्रक्रियाएं धीरे-धीरे घटती हैं और अंततः किसी के दैनिक कार्यों में बाधा डाल सकती हैं।

अलग-अलग तरीके से काम करती है माइक्रोग्लिया : अमेरिका के रोचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अल्जाइमर से ग्रस्त मादा और पुरुष चूहों के मस्तिष्क में माइक्रोग्लिया नामक प्रतिरक्षा कोशिकाएं अलग-अलग तरीके से काम करती हैं और मादा मस्तिष्क में नुकसान पहुंचाते हैं। जर्नल आफ न्यूरोइन्फ्लेमेशन में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि मादा चूहों में माइक्रोग्लिया एमीलाइड बीटा पट्टिकाओं के प्रति अधिक मजबूत इंटरफेरान रिस्पांस देते हैं। एमीलाइड बीटा पट्टिकाएं मस्तिष्क में प्रोटीन होता हैं जो अल्जाइमर रोग के रोगियों में चिपचिपे गुच्छों के रूप में जमा होती हैं।

न्यूरोइन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है इंटरफेरान : इंटरफेरान एक प्रकार का सिग्नलिंग प्रोटीन या साइटोकाइन्स है,

प्रतीकात्मक

जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए पैदा करती है। अध्ययनों से पता चला है कि इंटरफेरान न्यूरोइन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है और उन सिनेप्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जहां दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि जब मस्तिष्क में इम्यून सेल्स एमीलाइड बीटा पट्टिकाओं का उपभोग करती हैं, तो वे डीएनए या आरएनए के संपर्क में आ सकती हैं। कोशिकाओं को इंटरफेरान छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि मादा चूहों में माइक्रोग्लिया बड़े और अधिक असामान्य पट्टिकाएं छोड़ती हैं, जो पुरुष चूहों के मस्तिष्क की तुलना में अधिक न्यूरोनल कनेक्शनों या सिनेप्सों को नुकसान पहुंचाती हैं। रोचेस्टर विश्वविद्यालय की पहली लेखिका लिआ कैल्सिनेस रैड्रिगेज ने कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक था कि मादा माइक्रोग्लिया में इतना मजबूत इंटरफेरान रिस्पांस और ये इंटरफेरान प्रतिक्रियाशील माइक्रोग्लिया ज्यादा एमीलाइड बीटा का उपभोग कर रही थीं।

हार्मोन में उतार-चढ़ाव का प्रभाव नहीं : कैल्सीनेस रैड्रिग्ज ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि हमने महिलाओं में उनके साइकिल के अलग-अलग हार्मोनल स्टेज पर एमीलाइड बीटा पैथोलाजी या माइक्रोग्लिया जीन एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं देखा, जिससे पता चलता है कि हार्मोन में उतार-चढ़ाव से इन अंतरों को शायद नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क की इम्यून सेल्स में इंटरफेरान सिग्नलिंग अल्जाइमर से लड़ने के लिए लिंग विशिष्ट, व्यक्तिगत उपचार का लक्ष्य हो सकता है। लेखकों ने दिखाया कि एमीलाइड-बीटा पट्टी की आकृति में लिंग विशिष्ट बदलाव होते हैं और ओस्ट्रस चक्र के दौरान एंडोजेनस हार्मोनल उतार-चढ़ाव (एमीलाइड बीटा) माइक्रोग्लियल ट्रांसक्रिप्टोमिक प्रोफाइल को प्रभावित नहीं करते हैं। यह अध्ययन मादा माइक्रोग्लिया में (एमीलाइड-बीटा) के प्रति प्रतिक्रिया करते समय इंटरफेरान सिग्नलिंग के नए लिंग संवर्धन की पहचान करता है।

DAINIK JAGARAN PAGE NO- 18

भारत को आशा व विश्वास की नजरों से देख रही दुनिया

पीएम बोले, भारत ने पकड़ ली है सुधारों की रफ्तार, देश की जनसंख्या 'सुधार एक्सप्रेस' का प्राथमिक इंजन

कई प्रयासों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए इंटरनेट मीडिया पर साझा किए विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्ष 2025 की विदाई बेला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया है कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भविष्य का संकेत भी दिया। कहा कि हम आने वाले वर्षों में भी सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने प्रवासियों सहित अन्य देशों से आग्रह किया कि भारत की विकास यात्रा से अपना जुड़ाव और मजबूत करें। भारत पर भरोसा बनाए रखें और निवेश करते रहें। दो महीने बाद आने वाले आम बजट से पहले प्रधानमंत्री का यह संकेत खास महत्व रखता है।

इंटरनेट मीडिया लिंक्डइन पर मंगलवार को किए पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अगली पीढ़ी के सुधारों के माध्यम से प्रगति की गति बढ़ाने के लिए विश्व द्वारा सराहा जा रहा है। भारत अपने लोगों के नवाचार के उत्साह के कारण वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है। अब विश्व भारत को आशा और विश्वास के साथ देखता है।

जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हाल ही में मुख्य सचिवों के साथ बैठक में विचार-विमर्श कर चुके पीएम मोदी ने कहा कि वह कई लोगों से कहते रहे हैं कि भारत 'सुधार एक्सप्रेस' पर सवार हो चुका है। इस 'सुधार एक्सप्रेस' का प्राथमिक इंजन भारत की जनसंख्या, युवा पीढ़ी और देश के लोगों का अदम्य साहस है।

उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता और विश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना था। प्रधानमंत्री ने जीएसटी, भारतीय बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति सहित सुधारों के कुछ उदाहरण भी दिए। कहा कि जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब लागू किए गए हैं। इससे आम लोगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों आदि पर बोझ कम हुआ है।

पीएम ने याद दिलाया कि मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी गई है। पहली बार 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह 1961 के अप्रचलित आयकर अधिनियम के स्थान पर आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम, 2025 लाया गया है।

उन्होंने लघु उद्योगों की नई परिभाषा के अलावा संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए पांच समुद्री कानूनों, चार आधुनिक श्रम संहिताओं के रूप में श्रम कानून सुधार का भी उल्लेख किया। विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ गिनाने के साथ ही उन्होंने लिखा कि शांति अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा में शुरू किए गए सुधार भारत की स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विकसित भारत-जीरामजी अधिनियम, 2025 को भी ग्रामीण रोजगार गारंटी की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार भी याद दिलाए। बता दें कि विपक्ष विकसित भारत-जीरामजी अधिनियम, 2025 का पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन ने इसे श्रमिक हितैषी बताया है।

दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने को विभिन्न क्षेत्रों में मिशन रूप में सुधारों की जरूरत: मोदी

नई दिल्ली, प्रेट: दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में मिशन रूप में सुधार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के संदर्भ में नीति आयोग में जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत में यह बात कही। इस संवाद का विषय 'आत्मनिर्भरता एवं संरचनात्मक रूपांतरण: विकसित भारत के लिए एजेंडा' था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया और बजट निर्धारण में 2047 के लिए संकल्प को केंद्रीय रूप से रखा जाना चाहिए। देश की वैश्विक श्रम शक्ति और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाए रखना जरूरी है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प अब सरकारी नीतियों से इतर आम जन की आकांक्षा बन चुका है।

नई दिल्ली में मंगलवार को नीति आयोग में बजट-पूर्व बैठक में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट

बातचीत के दौरान अर्थशास्त्रियों ने मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने घरेलू बचत बढ़ाकर, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और नई तकनीक अपनाकर ढांचागत बदलाव को तेज करने पर बल दिया। इस दौरान डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) को लगातार बढ़ाने पर भी चर्चा की। इस चर्चा में कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों ने शिरकत की। इनमें शंकर आचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, एनआर भानुमूर्ति, अमिता बत्रा, जन्मेजय सिन्हा, अमित चंद्रा, रजनी सिन्हा, बसंत प्रधान, मदन सबनवीस, आशिमा गोयल, धर्मकीर्ति जोशी, उमाकांत दास, पिनाकी चक्रवर्ती, इंद्रनील सेन गुप्ता, समीरन चक्रवर्ती, अभिमान दास, राहुल बाजोरिया, मोनिका हलन और सिद्धार्थ सान्याल शामिल थे।

DAINIK JAGARAN PAGE NO

कुछ अलग | धूप-अगरबत्ती, पारंपरिक परिधानों के साथ बढ़ा रहीं व्यंजनों का स्वाद, समूह के सहारे राज्य में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहीं गृहिणियां

सरस मेला : गृहिणी से सफल उद्यमी बन रहीं ग्रामीण महिलाएं

टना, मुख्य संवाददाता। सूझबूझ और अपनी मेहनत से ग्रामीण महिलाएं गृहिणी से सफल उद्यमी बन रही हैं। अपने कारोबार को नई ऊंचाई दे रही हैं। घरों तक सीमित रहने वाली जीविका दीदी समूह से जुड़कर सफल हो रही हैं। कभी चूल्हा-चौका करने वाली ये ग्रामीण महिलाएं अब घरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार दे रही हैं। सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से अनगिनत महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। स्वरोजगार करके अपने घर की आर्थिक नींव को मजबूती प्रदान कर रही हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जीविका दीदी इन दिनों सरस मेले में उदाहरण के तौर पर नजर आ रही है। ये किराना, धूप-अगरबत्ती, वस्त्र, शृंगार के सामान, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टाल के साथ विलुप्त हो रहे शिल्प कला को सामने लाने का काम कर रही है। 12 दिसंबर से लगे मेला में अब तक 24 करोड़ से अधिक की खरीदारी हो चुकी है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित सरस मेला का आयोजन साल में दो बार होता है। मेले में ढाई सौ से अधिक समूह की महिलाओं ने स्टाल लगाए। ग्रामीण विकास विभाग सह परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका दीदियां उद्यमशीलता की मिसाल हैं। परियोजना से जुड़ने के बाद औसत वार्षिक आय बढ़ी है।

17 दिनों के मेले में 24 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ

गांधी मैदान में सरस मेले में मंगलवार को खरीदारी करती महिलाएं।

मिसाल | 1 | उन्नति जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य प्रेमलता देवी हर्बल अगरबत्ती और धूप का कारोबार करती है। पति का एक्सीडेंट होने और नौकरी छूट जाने के बाद उनकी माली हालत खराब हो गयी। जीविका से जुड़ी और अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण लिया। पर्यावरण फ्रेंडली अगरबत्ती बनाती है। कारोबार की बात करें तो महीने का तीन लाख रुपये हो जा रहा है।

मिसाल | 2 | श्रद्धा जीविका स्वयं सहायता समूह की निर्मला देवी की किराने की दुकान है। घरों में चौका-बर्तन का काम करने वाली निर्मला देवी जीविका से जुड़ने के बाद सफल उद्यमी है। पति की मृत्यु 2012 में हो गयी। घरों में चौका बर्तन का काम करके बच्चे को पढ़ा रही थी। जीविका से जुड़ने के बाद जीवन में सुधार हुआ। इस बार सरस मेले में पांच लाख का कारोबार कर चुकी हैं।

HINDUSTAN PAGE N0- 4

Useful For Mains

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नई संभावनाएं

नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के आकार लेने से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा व्यापार घाटे की चिंताएं भी कम होंगी।

जयंतीलाल भंडारी

अमेरिका की ओर से भारी-भरकम शुल्क लगाने के बावजूद भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) इस समय निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं अब नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अन्य कई देशों के साथ एफटीए के आकार लेने से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़ेगे और व्यापार घाटे की तमाम चिंताएं भी कम होंगी। हाल ही में जारी विदेश व्यापार के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 64.05 अरब डालर से बढ़ कर 73.99 अरब डालर हो गया। निर्यात में 15.52 फीसद की वृद्धि हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यापार समझौतों में नए श्रम कानून जान फूंकते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में भारत से निर्यात नई ऊंचाई पर होंगे। पिछले दिनों सरकार ने कहा कि भारत द्वारा किए गए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते से पेशेवर सेवाओं पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के कारण भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसर खुलेंगे और पेशेवर सेवाओं का निर्यात भी बढ़ेगा।

गौरतलब है कि हाल ही में 22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है और इस समझौते से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क सुनिश्चित किया गया है। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में अगले पंद्रह वर्षों में 20 अरब डालर के प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है। दूसरी ओर, भारत ने न्यूजीलैंड के 70 फीसद उत्पादों के लिए शुल्क में कमी की पेशकश की है, जो 95 फीसद द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को शामिल करती है। ऐसे में इस समझौते से 30 फीसद उत्पादों के लिए शुल्क खत्म हो जाएगा। इस समझौते के तहत लगभग 29.97 फीसद उत्पादों को सूची से बाहर रखा गया है। इनमें दूध, दही, पनीर, मांस और मछ के साथ अन्य पशु उत्पाद, चना, मक्का, बादाम, चीनी एवं प्याज जैसी वस्तुएं शामिल हैं। एफटीए लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के लिए भारत का शुल्क घट कर 13.18 फीसद हो जाएगा।

इस मुक्त व्यापार समझौते का मजबूत पक्ष भारत से सेवा निर्यात बढ़ाना और यहां से पेशेवरों को न्यूजीलैंड में अच्छे अवसरों के लिए आगे बढ़ाना भी है। यह समझौता भारत की प्रतिभाओं, नवउद्यम और नवाचार के लिए एक मजबूत बुनियाद प्रदान करता है। यह भारत के लिए सबसे प्रमुख सेवाओं की ऐसी पेशकश करता है, जो अब तक किसी भी पिछले समझौते में शामिल नहीं रहा है। यह समझौता न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों पर संख्या संबंधी सीमाओं को भी हटाता है। साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों के लिए तीन वर्ष तक और डाक्टरेट कर चुके विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के बाद चार साल तक न्यूजीलैंड में काम करने अवसर प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भारत के कुशल पेशेवरों के लिए मुक्त व्यापार समझौता एक नया अस्थायी रोजगार प्रवेश (टीईई) यानी वीजा प्रदान करता है। इसका लाभ उच्च मांग वाले क्षेत्रों के भारतीय पेशेवर ले सकेंगे।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के महज चार दिन पहले 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में मस्कट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान के उनके समकक्ष कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) कहा गया

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के महज चार दिन पहले 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के उनके समकक्ष कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीपा) कहा गया है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि ओमान के साथ समझौते के तहत भारत के 98 फीसद निर्यात को वहां के बाजार में शून्य शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इस समझौते से भारत के कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवाई, वाहन, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत-ओमान के बीच समझौते के तहत भारत के 98 फीसद निर्यात को ओमान के बाजार में शून्य शुल्क पर पहुंच मिलेगी। इस समझौते से भारत के कपड़ा, रत्न-आभूषण, दवाई, वाहन, कृषि उत्पाद और चमड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। खासतौर से भारत से करीब 3.64 अरब डालर के निर्यात पर ओमान में फिलहाल लगने वाला पांच फीसद शुल्क शून्य हो जाएगा। इसके बदले में भारत ने ओमान से आने वाले विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी सुनिश्चित की है।

ओमान से भारत आने वाले 95 फीसद उत्पादों के शुल्क कम होंगे। इनमें खजूर, मार्बल और 'पेट्रोकेमिकल' उत्पाद शामिल हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के हित में कई अहम बातें हैं। हमारे देश ने घरेलू हितों की रक्षा के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं। पेशेवर आवाजाही पर भी एफटीए में भारत के हित हैं। पहली बार ओमान ने भारतीय पेशेवरों की आवाजाही पर व्यापक रियायतें दी हैं। अब एक अप्रैल 2026 से भारत-ओमान समझौता लागू होने के बाद भारतीय उत्पाद और सेवा निर्यात ओमान में बढ़ सकेंगे और हमारा प्रतिकूल व्यापार असंतुलन कम होगा।

यह बात अहम है कि राजग शासन के दौरान मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति से संबंधित जो नए आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उनके मुताबिक जहां इन देशों के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा है, वहीं इन देशों में निर्यात भी बढ़ रहे हैं। वहां से भारत को अधिक निवेश प्राप्त हो रहा है। एक अक्तूबर से भारत और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफटा) के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। एफटा देशों को निर्यात बढ़ने लगे हैं। इसी तरह भारत और ब्रिटेन के बीच किए गया मुक्त व्यापार समझौता भी अहम है। पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ समझौते के विभिन्न पहलुओं पर रणनीतिक मंथन किया और कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसर बेजोड़ होंगे। इतना ही नहीं, नए वर्ष में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन पेरू, चिली, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और इजराइल सहित अन्य कई प्रमुख देशों के साथ भी व्यापार समझौते आकार लेते हुए दिखाई देंगे।

पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में 23वें भारत-रूस शिखर बैठक में भारत के साथ 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार बढ़ा कर सौ अरब डालर किया जाना सुनिश्चित करते हुए भारत-रूस मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातें तेजी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार और एफटीए के अधिकतम लाभ लेने और विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए एक अप्रैल 2026 से भारत में लागू किए जाने वाले नए श्रम कानून भी मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जिन नए श्रम कानूनों के तहत चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, उनसे श्रमिकों के लिए राहत और उद्योग-कारोबार के लिए आर्थिक रफ्तार का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। नए श्रम कानून के तहत चार श्रम संहिताएं- मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 शामिल हैं।

उम्मीद करना चाहिए कि नए वर्ष में सरकार दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आकार देने के साथ-साथ समझौते के लाभ को पाने के लिए देश के उद्योग-कारोबार और श्रम बल को नई दक्षता के साथ तैयार करेगी। ऐसे में यह भी उम्मीद करें कि ये समझौते भारत को वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की डगर पर आगे बढ़ाएंगे।

JANSATTA PAGE NO- 6

प्रधानमंत्री ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ मंथन किया

तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी बजट पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र विशेषज्ञों से मंगलवार को मुलाकात की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम, आयोग के अन्य सदस्य, कई अर्थशास्त्री तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञ मौजूद थे।

नई दिल्ली स्थित नीति आयोग के दफ्तर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। • एएनआई

मोदी और खेल जगत की हस्तियां शिरकत करेंगी

नई दिल्ली। महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर सहित चार शीर्ष खिलाड़ी नौ से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद (वीबीवाईएलडी) 2026 में भाग लेंगी। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को विकसित भारत की परिकल्पना को आकार देने में सार्थक भूमिका प्रदान करना है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगा, क्योंकि इसी दौरान संवाद करेंगे।

पुतिन ने नववर्ष के लिए दीं मुर्मु-मोदी को शुभकामनाएं

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित विश्व के नेताओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। रूसी सत्ता के केंद्र क्रेमलिन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि क्रिसमस और आगामी नव वर्ष 2026 के लिए ये शुभकामनाएं दी गईं।

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर मंगलवार को गहरी चिंता जताई। उन्होंने रूस-यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

HINDUSTAN PAGE NO- 20

भोजन की बर्बादी से पर्यावरण को भी खतरा

सुधीर कुमार

ब्राजील की राजधानी बेलेम में गत दिनों आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान भोजन की बर्बादी से पर्यावरण पर होने वाले खतरे को कम करने के निमित्त शुरू की गई 'फूड वेस्ट ब्रेकथ्रू' नामक पहल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इसका ध्येय 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना है, जिससे वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में सात प्रतिशत की गिरावट सुनिश्चित की जा सकती है।

दरअसल 30 लाख डालर की वित्तीय मदद से चार वर्ष के लिए बनाई जा रही इस परियोजना को दुनिया के विभिन्न शहरों में लागू किया जाएगा। भोजन की बर्बादी आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। निस्संदेह इसमें कमी लाकर जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के साथ-साथ खाद्य असुरक्षा और भुखमरी आदि समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, प्रतिदिन एक अरब टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। यह बर्बादी न केवल सामाजिक और मानवीय दृष्टि से चिंता का विषय है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरे उत्पन्न करता है। यूएनईपी के एक अनुमान के अनुसार, भोजन की बर्बादी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 10 से 14 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। अगर इसपर ध्यान नहीं दिया गया तो 2050 तक खाद्य अपशिष्ट का केवल मीथेन पर प्रभाव दोगुना हो सकता है, जिससे हमारी जलवायु और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मीथेन एक प्रदूषक है, जो दो दशक की अवधि में कार्बन डाइआक्साइड की तुलना में वातावरण का तापमान 20 गुना अधिक बढ़ा सकता है। ऐसे में भोजन की बर्बादी को रोककर न केवल पर्यावरण को प्रदूषित होने, बल्कि जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। ऐसा करना आर्थिक सबलता भी प्रदान कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार खाद्य अपशिष्ट की बर्बादी को रोककर प्रतिवर्ष एक ट्रिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय हानि को रोका जा सकता है। भोजन की बर्बादी केवल अन्न की बर्बादी नहीं होती, बल्कि जिस हिस्से का इस्तेमाल भुखमरी को खत्म करने के लिए किया जाना था, वह इस्तेमाल के बिना ही व्यर्थ हो जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों और मानव श्रम की हानि भी संलग्न है। कतीर होती जलवायविक दशाओं के कारण कम होते अनाजोत्पादन तथा आबादी के बढ़ते बोझ को देखते हुए भोजन की बर्बादी पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है।

भोजन की बर्बादी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 10 से 14 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है

जापान भोजन की बर्बादी में 2008 की तुलना में 31 प्रतिशत तक की कमी लाने में सफल रहा है। वहीं नीदरलैंड उपभोक्ता स्तर पर 23 और खुदरा स्तर पर 17 प्रतिशत भोजन की बर्बादी की कटौती में कामयाब रहा है। अन्य देश भी इसे लेकर गंभीर हैं। आखिर हम संजीदा कब होंगे?

(लेखक कोएएयू में शोधार्थी हैं)

DANIK JAGARAN PAGE NO- 8

विपक्ष के लिए बनते-बिगड़ते रहे हालात

राहुल वर्मा | फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

सिंहावलोकन- 2025

साल 2025 में राजनीतिक मोर्चे पर कुछ समस्याओं का हल निकला, तो कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी हुईं। अच्छी बात यह है कि देश में राजनीतिक स्थिरता की स्थिति बनी रही।

अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में नई संभावनाओं के आसार जगाए थे, तो 2025 के खत्म होते-होते उनमें से कुछ उम्मीदों पर एक तरह से अंकुश लगता नजर आया। हालांकि, कुछ नए मुद्दे परवान चढ़ते हुए भी दिखे।

सबसे बड़ी संभावना 2024 में जो दिखी, वह थी, लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगना और कांग्रेस की सीटें बढ़कर दोगुनी हो जाना। उस नतीजे से ऐसा लगा था कि कई वर्षों के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष को नया बल मिलने वाला है। मगर उसके बाद हालात धीरे-धीरे बदलते नजर आए, खासकर पिछले साल हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद।

साल 2025 भी इससे बहुत अलग नहीं रहा। वर्ष की शुरुआत में दिल्ली और अंत में बिहार विधानसभा की चुनावी जंग से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का वर्चस्व फिर से स्थापित हुआ, जिससे देश में विपक्ष के लिए बनने वाली जगह पर एक तरह से विराम-सा लग गया। अब देखना यह होगा कि साल 2026 के विधानसभा चुनावों से क्या तस्वीर निकलती है। क्या भाजपा नए राज्यों में अपना विस्तार कर पाएगी या कांग्रेस को नई संजीवनी मिलेगी या फिर क्षेत्रीय दल अपने सूबों में दबदबा बनाए रखेंगे?

दूसरा मसला राजनीतिक दलों के अंदरूनी हालात से जुड़ा है। साल 2025 के खत्म होते-होते भाजपा को नितिन नबीन के रूप में अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला, जो कम उम्र के हैं। यह उसी कवायद की अगली कड़ी है, जिसके तहत भाजपा इन दिनों अपने नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है। इसकी झलक हमने कुछ राज्यों (मसलन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली) में कम उम्र के मुख्यमंत्री के चयन के रूप में भी देखे हैं। अब इन नेताओं का प्रदर्शन तय करेगा कि पार्टी में बदलाव का यह दौर किस दिशा में आगे बढ़ेगा?

हालांकि, इसके मुकाबले दूसरे दलों को देखें, खासकर कांग्रेस को, तो उसके अंदर कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर कलह मची हुई है। चाहे वह रह-रहकर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया व उप-मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की आपसी जंग हो या फिर केरल में शशि थरूर की नाराजगी। यही बात बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को लेकर भी कही जा सकती है, जहां विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पार्टी के 'प्रथम परिवार' में 'गृह युद्ध' जैसी स्थिति बन गई। यानी, इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से मोदी-शाह के नेतृत्व में आगे बढ़ती नजर आई, तो वहीं अन्य पार्टियां इस मोर्चे पर संघर्ष करती दिखीं।

तीसरा पहलू चुनाव आयोग की साख और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठ रहे सवालों से जुड़ा है। आयोग पर साल 2024 से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे और महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो विपक्ष ने कथित 'वोट चोरी' का मुद्दा गरम रखा। हालांकि, चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर की घोषणा की और उसे पूरा भी किया, जिसके बाद 12 अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया चल रही है। मगर जिन राज्यों में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां काफी गहमागहमी है। बेशक, एसआईआर के बादबिहार में मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लेकिन इसे लेकर जनता के बीच से कुछ खास विरोध नहीं आया, इसलिए ऐसा लगता कि विपक्ष के इस आरोप में खास दम नहीं है कि कई सारे उन मतदाताओं के नाम भी सूची से कट गए हैं, जिनके नाम वास्तव में होने चाहिए थे। यहां तक कि बिहार में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी ही देखी गई। लिहाजा, अब नजर उन राज्यों पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा, वहां के मतदान पर इसका कितना असर पड़ता है?

चौथा बड़ा मसला चुनावों से ऐन पहले नकदी हस्तांतरण का है। पिछले कुछ चुनावों से तमाम राज्यों में यह प्रवृत्ति दिखी है। साल 2024 में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा इसके गवाह बने थे, तो 2025 में दिल्ली और बिहार। हालांकि, दिल्ली में तत्कालीन आप आदमी पार्टी की सरकार की यह कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी, क्योंकि पूर्ण राज्य न होने के कारण दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए उप-राज्यपाल व केंद्र सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। मगर बिहार की चुनावी जीत में इसका खासा योगदान माना गया। आंकड़े बताते हैं, पीछे दो वर्षों में सत्ता-विरोधी रुझान के बावजूद यदि सत्तारूढ़ दल विधानसभा चुनावों में अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे, तो इसमें मतदाताओं के बैंक-खाते में सामाजिक कल्याण के नाम पर डाली गई रकम ने बड़ी भूमिका निभाई। क्या यह प्रवृत्ति अगले साल भी बनी रहेगी? आसार तो यही लग रहे हैं।

आखिरी बात, जो इस तरह चुनाव से ठीक पहले नकद हस्तांतरण जैसी नीतियों से जुड़ी हुई है। आर्थिक विश्लेषक बताते रहे हैं कि ऐसी योजनाएं राज्यों की आर्थिक दशा को बिगाड़ सकती हैं। वैसे भी, घरेलू चुनौतियों को दरकिनार कर दें, तो वैश्विक आपूर्ति शृंखला में जिस तरह की रुकावटें बनी हुई हैं, उससे देश पर आर्थिक भार बढ़ा है। रही-सही कसर अमेरिकी सरकार की टैरिफ जंग ने पूरी कर दी है। नतीजतन, केंद्र सरकार ही नहीं, तमाम राज्य सरकारें भी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रही हैं। रुपये की कीमत में भी गिरावट जारी है। ऐसे में, सुधारों पर जोर देना जरूरी है।

इस साल श्रम कानूनों में सुधार और मनरेगा का नाम बदलकर उसे नए रूप में पेश करने की गंभीर कोशिश हुई है। इसका असर अभी दिखना बाकी है। हालांकि, औद्योगिकीकरण की बड़ी योजना इन दिनों नहीं दिख रही और देश में बेरोजगारों की फौज भी लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा, आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए गंभीर मेहनत की दरकार है।

कुल मिलाकर, साल 2025 में राजनीतिक मोर्चे पर मिली-जुली तस्वीर दिखी। कुछ समस्याओं का जहां हमने सफलतापूर्वक समाधान निकाला, तो कुछ नई चुनौतियां भी सामने आईं। मगर अच्छी बात है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति नहीं है। हालांकि, कुछ ऐसी मुश्किलें अवश्य हैं, जिन पर संजीदगी से ध्यान देने की जरूरत है। साल 2024 में जो संभावनाएं पैदा हुई थीं, वे 2025 में बनती-बिगड़ती रहीं, मगर 2026 को लेकर उनसे नई उम्मीदें भी पैदा हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इस पर कितना खरा उतर पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

HINDUSTAN PAGE NO - 16

डा. मोनिका राज
शोधार्थी

आजकल

शक्ति संतुलन के दौर में दुनिया

2025 ऐसा साल रहा जब दुनिया ने शक्ति के खुले प्रदर्शन, गहराती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बढ़ती अनिश्चितता को स्पष्ट रूप से देखा। विभिन्न क्षेत्रों में यह साफ दिखाई दिया कि बड़ी शक्तियां अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का आक्रामक रूप से उपयोग कर रही हैं। इन सभी ने यह संकेत दिया है कि शीतयुद्ध के बाद जिस स्थिर और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की उम्मीद की गई थी, वह गंभीर संकट में है

आकार ले रही नई विश्व व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता पर भारत का जोर। फाइल

बीत रहा वर्ष 2025 वैश्विक व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आया। यह ऐसा समय रहा जब दुनिया ने शक्ति के खुले प्रदर्शन, गहराती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बढ़ती अनिश्चितता को देखा। विभिन्न क्षेत्रों में यह साफ दिखाई दिया कि बड़ी शक्तियां अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का आक्रामक रूप से उपयोग कर रही हैं। अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां, रूस-यूक्रेन युद्ध का जारी रहना, इजरायल द्वारा लेबनान और गाजा में किए गए सैन्य अभियान तथा व्यापार युद्धों और टैरिफ नीतियों के दूरगामी प्रभाव ने मिलकर यह संकेत दिया है कि शीत युद्ध के बाद जिस स्थिर और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की उम्मीद की गई थी, वह गंभीर संकट में है। भारत जैसे उभरते देशों के लिए यह स्थिति एक साथ चुनौतियां भी लेकर आई है और अवसर भी, जिनसे निपटने के लिए संतुलित और दूरदर्शी रणनीति की आवश्यकता है।

2025 की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक अमेरिका की वह तत्परता रही, जिसके तहत उसने फिर से सैन्य बल के प्रयोग को प्राथमिकता दी। ईरान पर अमेरिकी हमलों ने यह संदेश दिया कि वाशिंगटन अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए एकतरफा कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। यह कदम केवल ईरान की क्षेत्रीय भूमिका या उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य उस अमेरिकी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना भी था, जो हाल के वर्षों में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। हालांकि इन कार्रवाइयों का परिणाम पश्चिम एशिया में अस्थिरता के और बढ़ने के रूप में सामने आया। तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों की चिंताएं और गहरी हो गईं। यह साफ हो गया कि बहुपक्षीय सहमति के बजाय अब शक्ति राजनीति ही वैश्विक घटनाओं की दिशा तय कर रही है।

इस बीच रूस-यूक्रेन युद्ध बिना किसी स्पष्ट समाधान के जारी है। जो संघर्ष शुरुआत में एक क्षेत्रीय युद्ध माना जा रहा था, वह अब वैश्विक प्रभावों वाला एक लंबा टकराव बन चुका है। यूरोप इस युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां ऊर्जा संकट, महंगाई और राजनीतिक मतभेदों ने कई देशों की आंतरिक स्थिरता को चुनौती दी है। इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुटों को और कठोर बना दिया है, एक ओर नाटो और उसके सहयोगी देश हैं तो दूसरी ओर रूस है, जिसे परोक्ष रूप से चीन और कुछ अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत सहित ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए यह युद्ध इस बात का सबक रहा है कि केवल नैतिक उपदेशों पर आधारित कूटनीति की सीमाएं होती हैं और रणनीतिक स्वायत्तता कितनी आवश्यक है। रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने का भारत का निर्णय इसी व्यावहारिक सोच का उदाहरण है।

इस वर्ष पश्चिम एशिया अशांति का प्रमुख केंद्र बना रहा। इजरायल द्वारा लेबनान और गाजा में की गई सैन्य कार्रवाइयों ने अनुपातिक बल प्रयोग, मानवीय कानूनों और फलस्तीन समस्या के समाधान में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता पर बहस को तेज कर दिया। संयम बरतने की लगातार अपीलों के बावजूद हिंसा नहीं रुकी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं तनाव को रोकने और शांति स्थापित करने में कितनी कमजोर हो चुकी हैं। अरब देशों के लिए यह स्थिति आंतरिक और क्षेत्रीय दबाव लेकर आई, जहां ईरान समर्थित गुटों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया। भारत, जिसके इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासी नागरिक रहते हैं और जिसके आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, को इन परिस्थितियों में बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। उसे इजरायल के साथ अपने मजबूत संबंधों, फलस्तीन के प्रति अपने पारंपरिक समर्थन और अरब देशों के साथ अपनी साझेदारियों के बीच संतुलन साधना पड़ा।

इस वर्ष सैन्य संघर्षों के अलावा आर्थिक दबाव और अमेरिका का टैरिफ भी एक प्रभावशाली हथियार के रूप में उभरे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों की वापसी ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था की नाजुकता को उजागर कर दिया। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के नाम पर लगाए गए शुल्कों ने न केवल विरोधी देशों, बल्कि सहयोगी देशों को भी प्रभावित किया। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं और लागत में वृद्धि हुई। भारत, जिसे अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार माना जाता है, वह भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रहा। कुछ निर्यात क्षेत्रों पर बढ़े हुए शुल्क और बाजार तक पहुंच को लेकर अनिश्चितता ने यह याद दिलाया कि बड़ी शक्तियों का आर्थिक राष्ट्रवाद मित्र देशों के रिश्तों को भी कमजोर कर सकता है। इन परिस्थितियों ने भारत को अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

इन बदलते समीकरणों के केंद्र में ग्लोबल साउथ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विकासशील देश अब बाजार या संसाधनों के स्रोत भर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अपनी राजनीतिक भूमिका और स्वतंत्र निर्णय क्षमता को खुलकर सामने ला रहे हैं। जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों का महत्व इसी कारण बढ़ा है, क्योंकि यहां गैर-पश्चिमी देश वैश्विक एजेंडे को प्रभावित कर सकते हैं। भारत की जी-20 अध्यक्षता और विकास, जलवायु वित्त तथा समावेशी विकास पर उसका जोर कई देशों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। हालांकि वैश्विक शासन व्यवस्था के विखंडन के कारण व्यापक सहमति बनाना कठिन हो गया है, जिससे इन मंचों की प्रभावशीलता भी सीमित होती जा रही है।

2025 में चीन की भूमिका भी जटिल और प्रभावशाली बनी रही। बीजिंग ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचते हुए आर्थिक पहलों, रणनीतिक निवेशों और कूटनीतिक सक्रियता के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार जारी रखा। रूस को उसका संतुलित समर्थन प्रमुख शक्ति गुटों के बीच बढ़ते विभाजन को और गहरा करता गया। ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बना रहा, जिससे संभावित संघर्ष का खतरा मंडराता रहा। भारत के लिए चीन सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि सीमा विवाद अब भी कायम हैं और एशिया एवं ग्लोबल साउथ में प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। इसी कारण भारत अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के और करीब आया। हालांकि उसने औपचारिक सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखी।

सबके साथ संतुलित संबंध भारत की नीति

इस वर्ष भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आकांक्षा का संतुलित मिश्रण रही। भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता पर लगातार जोर दिया और किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल होने से इन्कार किया। साथ ही यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ाया। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ के लिए भारत की पहल ने उसे एक जिम्मेदार और रचनात्मक शक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि लगातार ध्रुवीकृत होती दुनिया में विविध संबंधों को संतुलित करना आसान नहीं रहा और इसके लिए निरंतर कूटनीतिक सूझबूझ की आवश्यकता पड़ी। इस अशांत वैश्विक माहौल में आर्थिक मजबूती भारत की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रही। युद्धों, प्रतिबंधों और टैरिफ नीतियों से हुए व्यवधानों ने ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया। विनिर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने से जुड़ी पहलों को नई गति मिली। भारत यह भी समझता रहा कि पूर्ण अलगाव कोई समाधान नहीं है और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। असली चुनौती यह रही कि खुलेपन और सुरक्षा के बीच ऐसा संतुलन कैसे बनाया जाए, जिसमें अत्यधिक जोखिम न हो। यह कार्य बड़ी शक्तियों की अनिश्चित नीतियों के बीच और भी कठिन हो गया।

2025 में वैश्विक संघर्षों का मानवीय पक्ष भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन, गाजा और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में आम नागरिकों की पीड़ा ने यह याद दिलाया कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या, खाद्य असुरक्षा और अनाज एवं उर्वरकों की आपूर्ति में बाधा का असर सबसे अधिक गरीब देशों पर पड़ा है। ऐसे समय में भारत द्वारा मानवीय सहायता, आपदा राहत और विकास सहयोग पर दिया गया जोर उसकी अंतरराष्ट्रीय भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। इससे यह संदेश गया है कि नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

इस तरह से 2025 ऐसा वर्ष साबित हुआ है जब वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियां स्पष्ट रूप से सामने आ गईं। सैन्य संघर्ष, आर्थिक राष्ट्रवाद और संस्थागत जड़ता ने सहयोग और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था की कल्पना को कमजोर कर दिया है। शक्ति राजनीति एक बार फिर केंद्र में आ गई है, जिससे देशों को अधिक कठोर और अनिश्चित वातावरण में स्वयं को ढालना पड़ रहा है। भारत के लिए यह दौर रणनीतिक स्वायत्तता, विविध साझेदारियों और आंतरिक मजबूती के महत्व को रेखांकित करता है। भले ही वैश्विक परिदृश्य जोखिमों से भरा हुआ हो, लेकिन इसमें उन देशों के लिए अवसर भी हैं, जो व्यावहारिक सोच के साथ स्पष्ट उद्देश्य को जोड़ने में सक्षम हैं। भारत और अन्य उभरती शक्तियां इस उथल-पुथल भरे समय को कैसे दिशा देती हैं, इसी पर निर्भर करेगा कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था किस रूप में सामने आती है। **-डा. मोनिका राज**

डा. सुशील कुमार सिंह
लोककार एवं प्रशासनिक चिंतक

सुशासन की रीढ़ है नैतिकता

बीते 25 दिसंबर को देश ने सुशासन दिवस मनाया। सुशासन को कागजों से जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारों में नैतिकता का होना अनिवार्य है। नव वर्ष में लोकसेवकों और सत्ताधारियों में इसका समावेश हो, इसके लिए जरूरी पहल की जानी चाहिए। अधिक शक्ति या सत्ता के साथ अधिक जिम्मेदारी भी आती है। जिस प्रकार दायित्व की पूर्ति के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार नीतियों को कारगर तरीके से प्रसारित कर जनहित को सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता अनिवार्य है। एक सक्षम प्रशासक में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ पारदर्शिता का समावेशन हो तो बात सुशासन से युक्त हो जाती है। हालांकि आचरण नीति केवल सिविल सेवकों के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम कार्यकारियों के लिए व्यापक रूप में होनी चाहिए, जो राष्ट्र और राज्य में ताकतवर हैं और वैधानिक सत्ता से पोषित हैं, साथ ही देश बदलने की इच्छाशक्ति तो रखते हैं, लेकिन लोभ और लालच से मुक्त नहीं हैं। नोलन की सुशासन संहिता में निष्पक्षता, तटस्थता एवं आत्मसंयम से लेकर जनसेवा के प्रति समर्पण समेत 15 अच्छे आचरण के सिद्धांत निहित हैं। वास्तव में आचार नीति मानव चरित्र और आचरण से संबंधित है। यह सभी प्रकार के झूठ की निंदा करती है। इसे देखते हुए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आचार नीति पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता से संबंधित कई सिद्धांतों को उकेरा था। पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से उत्पन्न होती हैं? यह कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार-मुक्त नैतिक समाज के लिए इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और 'मैं क्या दे सकता हूं' की भावना से इस स्थिति को बदलना होगा।

इस बात को बिना दुविधा के समझ लेना ठीक होगा कि देश तभी ऊंचाई को प्राप्त करता है, जब शासन में आचार नीति सतही नहीं होती, बल्कि पूरी व्यवस्था इससे सराबोर रहती है।

नव वर्ष में भारत को नई सुशासन संहिता की आवश्यकता। प्रतीकात्मक

जिम्मेदारी और जवाबदेही आचार नीति के अभिन्न अंग हैं और यही सुशासन की पराकाष्ठा भी है। आचार नीति एक ऐसा मानक है, जो बहुआयामी है और यही कारण है कि यह दायित्वों के बोझ को आसानी से सह लेती है। यदि दायित्व बड़े हों और आचरण के प्रति गंभीरता न हो तो जोखिम बड़ा होता है। लोक प्रशासन में नैतिकता के पारितंत्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों के माध्यम से इसे व्यापक रूप दिया गया है। 1930 के दशक में ब्रिटिश सिविल सेवकों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' निर्देशों का एक संग्रह जारी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी आचार नीति का निर्माण इसी पारितंत्र का हिस्सा था। संविधान में काम-काज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा वर्ष 2001 में प्रशासन में ईमानदारी को लेकर जारी परामर्श पत्र में कई विचार और संस्थागत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें बेनामी लेन-देन, अवैध रूप से सिविल सेवकों द्वारा अर्जित संपत्तियां आदि शामिल थे।

गौरतलब है कि सुशासन विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। शासन में ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा का सुनिश्चित होना सुशासन की गारंटी है। सुशासन के चलते ही आचार नीति को भी एक आवरण मिलता है। दूसरे शब्दों में, अच्छे आचरण से शासन सुशासन की राह पकड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति बनाई गई, जिसे नोलन समिति के रूप में जाना जाता है, जिसमें सात मुख्य बातें-निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व शामिल थीं। देश में संस्थागत और कानूनी ढांचा कमजोर नहीं है, दिक्कत इसके अनुपालन करने वाले आचरण में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआइ, कैग, लोकपाल और लोकायुक्त जहां सुशासन स्थापित करने वाले संस्थान हैं, वहीं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना का अधिकार जैसे कई कानून मौजूद हैं। गौरतलब है कि सुशासन की पराकाष्ठा की प्राप्ति हेतु एक ऐसी आचार नीति की आवश्यकता है, जो संस्कृति, पर्यावरण तथा स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के अलावा आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बल दे। हालांकि ऐसी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान हैं, मगर अनुपालन के लिए एक नई संहिता की आवश्यकता है।

अब नए साल में नए भारत को नई सुशासन संहिता चाहिए, जिससे नैतिकता के समुचित तंत्र को विकसित किया जा सके। यह सच है कि जनता और मीडिया मूकदर्शक नहीं हैं, साथ ही न्यायिक सक्रियता भी बढ़ी है। बावजूद इसके, वह सवाल जो हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है, वह है कि लोकतंत्र के प्रवेश द्वार पर अपराध कैसे रुके और वैधानिक सत्ताधारक आचार नीति में पूरी तरह कैसे बंधें?

मंथन

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

संकट में पर्यावरणीय घटक

स्वस्थ और स्वच्छ जीवन का अधिकार मनुष्य, नदियों और विभिन्न जीवधारियों को संविधान से प्राप्त है। आज आवश्यकता है कि शासन-प्रशासन संवैधानिक जीवन अधिकारों की रक्षा करे

प्रकृति-पर्यावरण सुरक्षित होंगे तो ही जीवन सुरक्षित हो सकेगा। फाइल

जल, वायु, नदियां, समुद्र, धरती, पहाड़, जंगल, ग्लेशियर, विभिन्न जीव-जंतु और वनस्पतियां आदि पर्यावरणीय घटक हैं। ये विभिन्न घटक आज गंभीर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। इन घटकों का विकृत होना मानव सहित समूची जीव-सृष्टि के लिए खतरा बनता जा रहा है। विगत लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद गंभीर श्रेणी में चल रही है। प्रदूषण की अधिकता ने हवा को जहरीला बना दिया है। इससे शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिकी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। यूके स्थित भारतवंशी डाक्टरों ने वायु प्रदूषण को कोविड महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया है। वाहनों, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों की धूल, धुआं एवं घातक रसायन जीवन पर भारी पड़ रहे हैं। सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर की नई रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि देश के करीब 78 प्रतिशत ताप बिजली संयंत्रों में सल्फर डाइआक्साइड को नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं है और प्रदूषण फैलाने में ताप बिजली संयंत्रों की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या इन्हें मानकों के अनुरूप संचालित करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है?

गंगा, यमुना, हिंडन आदि सैकड़ों नदियां भयंकर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। महानगरों का अशोधित सीवेज और औद्योगिक कचरा सीधे नदियों में गिर रहा है। विडंबना यह भी है कि विभिन्न प्रदेशों में सीवेज शोधन हेतु एसटीपी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। जितने हैं, वे भी समुचित रूप में काम नहीं कर रहे हैं। शासन-प्रशासन की सुस्ती से यह स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अकेले उत्तर प्रदेश में गंगा एवं सहायक नदियों में 225 नाले सीधे मिल रहे हैं और लगभग 1100 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन सीधे नदियों में गिर रहा है। बंगाल के 27 शहरों में कुल 41 एसटीपी हैं, जिनमें से अधिकांश मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में केवल 20 एसटीपी के सहारे ही काम चल रहा है। दिल्ली में भी 37 एसटीपी हैं, जिनमें से लगभग 16 ही क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं। दिल्ली सहित देश के विभिन्न महानगरों में छोटे-बड़े सैकड़ों नाले सीधे नदियों में गिर रहे हैं। पूरे देश में औद्योगिक अपशिष्ट शोधन प्रणालियों की हालत तो और भी गंभीर है। ये सभी नदियां भिन्न-भिन्न रूपों में जीवनदायिनी हैं। क्या पूरे देश में नदियों की बदहाली गंभीर चिंतन का विषय नहीं है?

वन क्षेत्र धरती के फेफड़े कहे जाते हैं, लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। प्रत्येक वर्ष करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनके संरक्षण-संवर्धन की समुचित योजनाएं नहीं हैं। हाल ही में राज्यों द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश के 25 राज्यों में 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण है। 10 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने वन क्षेत्र पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी नहीं दी है। क्या यह स्थिति गंभीर नहीं है? जल के महत्वपूर्ण स्रोत ग्लेशियर भी प्रदूषण की गिरफ्त में हैं। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में विभिन्न ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और झीलें संवेदनशील बनी हुई हैं, जिससे बड़ी आपदाएं आ रही हैं। केदारनाथ आपदा और हाल में धराली-थराली की आपदाएं इसके प्रमाण हैं। बोतलें, पालिथीन, खिलौने आदि के रूप में प्लास्टिक स्थूल और सूक्ष्म रूप में पर्यावरणीय घटकों को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है। कूड़े के रूप में प्लास्टिक के संग्रहण एवं निस्तारण की समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं। लोग प्लास्टिक और कूड़े को यहां-वहां डाल देते हैं, इकट्ठा करके आग लगा देते हैं अथवा जल स्रोतों में फेंक देते हैं। क्या यह पर्यावरण और जीवन के लिए घातक नहीं है?

रसायनों एवं खाद के अधिकाधिक प्रयोग से धरती का स्वास्थ्य निरंतर गड़बड़ा रहा है, भूजल प्रदूषित हो रहा है। अनाज एवं औषधियों की गुणवत्ता घट रही है। मनुष्य सहित सभी जीवधारियों के स्वास्थ्य पर इसके घातक प्रभाव पड़ रहे हैं। पहाड़ भी निरंतर विकृति का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में सैकड़ों स्थानों पर वैध-अवैध खनन जारी है। क्या आज हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण-समावेशी विकास की ओर नहीं बढ़ना चाहिए?

स्वस्थ और स्वच्छ जीवन का अधिकार मनुष्य, नदियों और विभिन्न जीवधारियों को संविधान से प्राप्त है। इसलिए आज आवश्यकता है कि शासन-प्रशासन संवैधानिक जीवन अधिकारों की रक्षा करे। साथ ही विभिन्न पर्यावरणीय घटकों की स्थिति पर समग्रता में विचार करते हुए उनके संरक्षण-संवर्धन हेतु व्यापक और सतत योजनाएं बनाकर उन्हें तत्काल लागू किया जाए। पर्यावरणीय घटकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कड़े दंड के प्रविधान तत्काल लागू हों। ध्यान रहे, प्रकृति-पर्यावरण सुरक्षित होंगे तो ही जीवन सुरक्षित हो सकेगा।

DAINIK JAGARAN PAGE NO-9

साइंस सिटी से विज्ञान के सिद्धांत समझने में सुविधा होगी : नीतीश

परिसर में वैज्ञानिक प्रदर्शों का अवलोकन किया

21 एकड़ के भूखंड पर बनी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस सिटी का निरीक्षण किया
- सुविधाओं-व्यवस्थाओं की ली जानकारी, बच्चों से बात की

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि साइंस सिटी से छात्रों को विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी। विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ेगी।

वह मंगलवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस सिटी बहुत अच्छा बना है। यह विज्ञान और नवाचार का एक ऐसा आधुनिक केन्द्र है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहा है। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जानने-समझने के लिए यह आकर्षक और अनूठा केन्द्र है। युवा वर्ग के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। यहां आने वाले छात्र-छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातों, गतिविधियों को सरलता से समझने में सुविधा होगी। सीएम ने राजेन्द्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर नवनिर्मित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर एवं विभिन्न गैलरियों, वैज्ञानिक प्रदर्शों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। सीएम ने बच्चों से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष पराशर, डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। भवन निर्माण के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को साइंस सिटी में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

> देखें P 02

HINDUSTAN PAGE NO- 1

कैमूर जिले की मिलों से बिहार में पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति शुरू

अन्य जिलों में आपूर्ति जल्द, पोषणयुक्त चावल की कमी से धान कुटाई में हो रही थी देरी

- सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
- कहा- जरूरत पड़ने पर डीएम बढ़ाएंगे क्रय केंद्र

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में पोषणयुक्त चावल (एफआरके) की कमी दूर कर ली गई है। मंगलवार को कैमूर की मिलों को आपूर्ति शुरू कर दी गई है। जल्द ही अन्य जिलों की मिलों को भी आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद धान खरीद में तेजी आएगी। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने मंगलवार को विभागीय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।

बता दें कि एफआरके की कमी के चलते धान खरीद के दो माह बाद भी एक छटांक चावल एसएफसी के गोदामों तक नहीं पहुंचा है। इसके चलते धान कुटाई नहीं हो रही है। पैक्स के गोदाम भरे पड़े हैं। किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। पैक्स, व्यापार मंडल धान खरीद में आनाकानी कर रहे थे। अब खरीद में तेजी आएगी। मंत्री ने बताया कि राज्य में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है। इस वर्ष 36.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य बिहार को दिया गया है। इसे 45 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध केंद्र से किया गया है। अब तक 6620 समितियों ने राज्य के 1.32 लाख किसानों से 9.53 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। किसानों को 1755 करोड़ का भुगतान हुआ है। मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डीएम क्रय केंद्र की संख्या बढ़ा सकते हैं। किसानों की समस्या समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मौके पर विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, अपर सचिव अभय कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

पोर्टल से खरीद में था पेच

पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति पहले स्थानीय स्तर पर जांच के बाद कर दी जाती थी। अब पोर्टल के जरिए आपूर्ति की नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था की प्रक्रिया में देरी के चलते मिलों को आपूर्ति में देरी हो रही थी। मिलों को निर्देश है कि पोषणयुक्त चावल मिलाने के बाद ही एसएफसी को आपूर्ति करें। इस कारण मिलों ने धान कुटाई शुरू नहीं की है।

दो से सदस्यता अभियान चलेगा

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी पंचायतों में दो जनवरी से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए सदस्यता अभियान भी शुरू होगा।

सहकारिता विभाग दो चीनी मिल चलाएगा

मंत्री ने कहा कि राज्य की दो बंद पड़ी चीनी मिलों सकरी और रैयाम को सहकारिता विभाग चलाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तर पर विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को मिल ट्रांसफर होने के बाद सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

1.39 लाख किसानों को मिलेगी फसल सहायता

मंत्री ने बताया कि खरीफ 2024 के लिए 1.39 लाख किसानों को 124 करोड़ फसल सहायता राशि दी जाएगी। सत्यापन पूरा हो गया है। इसके अलावा रबी 2025-26 के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

HINDUSTAN PAGE NO- 2

जल संसाधन | बराज और डैमों की सुरक्षा का मूल्यांकन शुरू हुआ, सूबे के नहरों को नया जीवन देने की 250 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई, ओपीआरएमसी की तर्ज पर नहरों का मेंटेनेंस होगा

कोसी नहर परियोजना आधुनिकीकरण को हरी झंडी मिली

अलविदा 2025

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। इस वर्ष सिंचाई और बाढ़ प्रक्षेत्र में सूबे में कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए हैं। पुराने बराज और डैमों का सुरक्षा मूल्यांकन शुरू हो गया है। कोसी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण की योजना को मंजूरी देने के साथ-साथ नहरों से भूजल रिचार्ज करने की योजना पर काम शुरू किया गया है।

सूबे में नहरों की मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग का मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया है। सूबे के नहरों को नया जीवन देने की 250 करोड़ की योजना मंजूर की गयी। बक्सर-कोईलवर गंगा तटबंध पर सड़क बनाने की योजना बनी। सूबे की नहर प्रणालियों में स्काडा सिस्टम लगाने की योजना स्वीकृत हुई।

सूबे की दोनों सबसे अहम नहर परियोजनाएं पश्चिमी व पूर्वी कोसी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण के लिए 14114 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। इनका निर्माण तीन साल के अंदर किया जाना है। इनसे बाढ़ की समस्या दूर होने के साथ-साथ सिंचाई सुविधा का विकास होगा। पश्चिमी कोसी नहर के लिए 7832 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत है, जबकि पूर्वी कोसी नहर के लिए 6282 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। इसके तहत पूर्वी कोसी नहर का 41 किलोमीटर लंबाई में रिमॉडलिंग होगा। 117 किमी आगे तक उसका विस्तार भी किया जाएगा।

भूजल स्तर बेहतर बनाने का काम शुरू: नहरों के माध्यम से भूजल स्तर को भी बेहतर बनाने पर काम शुरू किया गया। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो रही है। यहां कई प्रखंडों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। विभाग के अनुसार आगे अन्य जिलों में भी इसे क्रमबद्ध रूप में लागू किया जाएगा। सूबे में नहरों में मेंटेनेंस के लिए पथ निर्माण विभाग का मॉडल लागू होगा। पथ निर्माण विभाग के ओपीआरएमसी की तर्ज पर नहरों का मेंटेनेंस होगा। दरअसल, जल संसाधन विभाग की ओर से सूबे में नयी नहर संपोषण नीति बनाने की तैयारी है। इसी लक्ष्य को लेकर विभाग ने पथ निर्माण विभाग के ओपीआरएमसी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है।

दोनों ओर 47 किमी तटबंध बनेगा: जानकारी के अनुसार मसान नदी पर की बायीं ओर 27 किलोमीटर, जबकि दायीं ओर 20 किमी लंबा तटबंध बनाया जाएगा।

कोसी नहर परियोजना के लिए 14114 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, नहरों की मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग का मॉडल लागू करने का निर्णय

दो नदियों पर तटबंध

हर साल बाढ़ से तबाही मचाने वाली सिकरहना व मसान नदियों पर तटबंध बनाने का फैसला हुआ। दोनों नदियों पर 103 किमी लंबा तटबंध बनेगा। इनके निर्माण पर 455 करोड़ खर्च होंगे। सिकरहना नदी पर 56 किमी लंबा तटबंध बनेगा। इनके निर्माण पर 240 करोड़ खर्च किये जाएंगे, जबकि मसान नदी पर 215 करोड़ की लागत से तटबंध जाएगा।

डैम की क्षमता का हो रहा आकलन

राज्य सरकार ने सारे बराज और डैमों के सुरक्षा मूल्यांकन का काम भी इस साल शुरू किया। देशभर के विशेषज्ञ बिहार के सभी बराज तथा डैम का सुरक्षा मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके तहत वे डैम की वास्तविक स्थिति का जमीनी आकलन करेंगे। उसकी क्षमता का परीक्षण भी किया जाएगा। देखा जाएगा कि इनकी मूल क्षमता पहले कितनी थी और आज कितनी रह गयी है। विशेषज्ञों के मूल्यांकन परिणाम के आधार पर राज्य के 34 डैम और बराज की सुरक्षा को लेकर विस्तृत कार्ययोजना बनेगी।

गंगा के तटबंध पर सड़क का निर्माण होगा

गंगा नदी के तटबंध पर नयी सड़क बनेगी। बक्सर-कोईलवर गंगा तटबंध पर बनने वाली 51 किमी लंबी यह सड़क कई शहरों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। निर्माण सरीमपुर और नैनीजोर के बीच होना है। तटबंध का निर्माण तो बक्सर जिला में ही होगा, लेकिन यह आरा, शाहपुर, बिहिया, डुमरांव को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। भविष्य में पटना से बक्सर के बीच भी वैकल्पिक मार्ग देगा।

HINDUSTAN PAGE NO- 2

मिशन 2036 | बिंद्रा की अध्यक्षता वाले नौ सदस्यीय कार्यबल ने खेल प्रशासन की कमियां बताने के साथ इनमें सुधार करने के लिए कई सिफारिशें भी कीं

प्रशासनिक कमियां दूर हों तो शीर्ष दस खेल देशों में आ सकेगा भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में खेल मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल ने भारत में खेल प्रशासन की कमियों को रेखांकित किया है। साथ ही उसने प्रशासनिक अधिकारियों समेत खेलों के विशेष पेशेवर कैडर को ट्रेनिंग देने के लिए स्वायत्त वैधानिक इकाई बनाने की सिफारिश भी की है।

मंडाविया को रिपोर्ट सौंपी: कार्यबल ने 170 पन्नों की अपनी रिपोर्ट खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंप दी है। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, भारत के खेल 'इकोसिस्टम' को पेशेवर बनाने के अपने प्रयास के तहत कार्यबल की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा। ओलंपिक 2036 तक भारत को शीर्ष दस खेल देशों में शामिल करने के लक्ष्य के तहत खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघों और प्रदेश संघों के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने, कमियों को तलाशने और सुधार के उपायों के लिए इस कार्यबल का गठन किया था।

नौ सदस्यीय कार्यबल इस साल अगस्त में बनाया गया था जिसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज बिंद्रा के अलावा आदिले सुमरिवाला और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के पूर्व सीईओ कमांडर राजेश राजगोपालन भी शामिल थे।

रिपोर्ट की अहम बातें

- खेल प्रशासकों में पेशेवर कैडर का अभाव है और संस्थागत निरंतरता भी कमजोर है। ट्रेनिंग के मौके व्यवस्थित और आधुनिक नहीं हैं।
- खिलाड़ियों के रिटायर होने के बाद खेल प्रशासन में आने के रास्ते सीमित हैं चूंकि अधिकांश खिलाड़ियों में इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव है। खेल प्रशासन में डिजिटल टूल और विश्लेषण का प्रयोग कम है।
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महासंघों की कार्यकारी समिति में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो जाएगा पर उन्हें प्रशासनिक कौशल की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था नहीं है।
- खिलाड़ियों के दीर्घकालिक विकास मॉडल के साथ करियर का कोई संगठित दोहरा रास्ता नहीं है जिससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और प्रशासन कौशल का विकास हो सके।
- साइ और प्रदेश विभागों के पास कोई समर्पित खेल प्रशासन सेवा नहीं है। सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों या अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों द्वारा ये भूमिकाएं निभाई जा रही हैं जिनके पास विशेष कौशल का अभाव होता है।
- अधिकांश महासंघों में अध्यक्ष के पास संचालन, वित्त और नियुक्तियों के अधिकार हैं जो वैश्विक प्रचलन के विपरीत है। चुने हुए पदाधिकारी संचालन की जिम्मेदारी ले लेते हैं जबकि उन्हें खेल प्रबंधन की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होती।

कार्यबल की सिफारिशें

- कार्यबल ने खेल प्रशासकों की क्षमता मजबूत करने के लिए पांच स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल शुरू करने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य विभागों को कैडर संरचना, पाठ्यक्रम अपनाने, डिजिटल सक्षमता और एथलीट मार्गों में संस्थागत परिपक्वता का आकलन करने में सक्षम बनाना है।
- खेल नीतियों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की भूमिका को देखते हुए उनके प्रशिक्षण में खेल शासन प्रशिक्षण मॉड्यूल को एकीकृत करने की सिफारिश की गई है।
- खेल शिक्षा और सामर्थ्य निर्माण राष्ट्रीय परिषद के गठन की अनुशंसा। यह मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई के रूप में काम करेगी।

HINDUSTAN PAGE NO- 19

दायित्व बोध का संकट

शिवम भारद्वाज

हाल ही में लखनऊ में जिस तरह के दृश्य सामने आए, वह उस व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति का आईना है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान सजावट के लिए लगाए गए पौधों को जिस सहजता से तथाकथित सभ्य लोगों ने उठा लिया, उसने एक असहज सवाल खड़ा किया है कि विकास की भाषा धाराप्रवाह बोलने वाले हम लोग, क्या अपने नागरिक होने का अर्थ भूलते जा रहे हैं! यह घटना इसलिए भी विचलित करती है क्योंकि इसमें वे लोग शामिल नहीं थे, जिनके लिए मजबूरी या अभाव का तर्क दिया जा सके। गमले उठाने वाले वैसे लोग थे, जिन्हें समाज संपन्न, शिक्षित और 'सभ्य' मानता है। जब लाखों रुपए की गाड़ी रखने वाला व्यक्ति कुछ सौ रुपए का सरकारी गमला उठाकर ले जाता है, तो यह उस मानसिकता की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें सार्वजनिक वस्तु को 'मुफ्त का माल' समझ लिया जाता है। यह आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक दरिद्रता का भी लक्षण है।

हम अक्सर यह मान लेते हैं कि शिक्षा, आय और आधुनिक जीवन-शैली अपने साथ अनुशासन और नैतिकता भी ले आती है, लेकिन ऐसी घटनाएं इस भ्रम को बार-बार तोड़ती हैं। सच यह है कि संपन्नता और संस्कार के बीच कोई स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। कई बार सुविधा और ताकत का अहसास व्यक्ति को नियमों से ऊपर होने का भ्रम दे देता है। यही भ्रम सार्वजनिक जीवन को सबसे गहरी चोट पहुंचाता है, क्योंकि इससे नागरिक जिम्मेदारी आत्मसात होने के बजाय धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है।

भारतीय संविधान नागरिकों को केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि उनके कर्तव्य भी स्पष्ट करता है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक दायित्व है, लेकिन व्यवहार में हमने अधिकारों को प्राथमिकता और कर्तव्यों को औपचारिकता बना लिया है। अधिकारों की बात आते ही हम मुखर हो जाते हैं, लेकिन कर्तव्यों की चर्चा होते ही चुप्पी साध लेते हैं। यही असंतुलन समाज के नैतिक ढांचे को भीतर से खोखला करता है।

कुछ समय पहले भी लखनऊ में ही आम महोत्सव के दौरान प्रदर्शनी में सजाकर रखे गए आमों को लोगों ने लूट लिया था। वह भी किसी अव्यवस्थित या अभावग्रस्त भीड़ का आचरण नहीं था, बल्कि उन्हीं नागरिकों का था, जिन्हें ऐसे आयोजनों का जागरूक दर्शक और उपभोक्ता माना जाता है। इससे पहले बड़े आयोजनों के दौरान गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में सार्वजनिक स्थलों से फूल-पौधों की चोरी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। महंगी गाड़ियों में इन चीजों की चोरी की तस्वीरें और वीडियो सुर्खियों में आए थे। इसी तरह एक राजनीतिक रैली में लोग खाट लेकर भागते दिख रहे थे। समस्या किसी एक आयोजन या प्रशासनिक चूक की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता का परिणाम है, जो सार्वजनिक स्थान को 'सरकारी' और 'बेपरवाह इस्तेमाल' की वस्तु मान लेती है।

हम निजी बातचीत में भ्रष्टाचार, व्यवस्था की खामियों और प्रशासन की विफलताओं पर खुलकर चर्चा करते हैं, नेताओं और अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब अपने आचरण की बारी आती है, तो हम वही करते हैं जो हमें सुविधाजनक लगता है। हम अक्सर उन देशों की प्रशंसा करते हैं, जहां सड़कें साफ हैं, कतारें अनुशासित हैं और सार्वजनिक व्यवस्था सुचारु है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह नागरिकों के रोजमर्रा के छोटे-छोटे निर्णयों का फल है- कचरा जहां-तहां न फेंकने, नियम न तोड़ने और जो अपना नहीं है, उसे न छूने का निर्णय। सभ्यता इन्हीं निर्णयों से बनती है। वहां व्यवस्था केवल कानूनों से नहीं, बल्कि नागरिकों के आत्म-अनुशासन से चलती है। सार्वजनिक स्थल वहां सरकार की नहीं, नागरिकों की भी जिम्मेदारी होते हैं।

यह समझना जरूरी है कि सड़कें, उद्यान, स्मारक और सार्वजनिक स्थल किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं हैं। ये हमारे ही कर या टैक्स के पैसों से बने हमारे साझा स्थान हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाना आखिर अपनी ही सामूहिक संपदा को क्षति पहुंचाना है। यह वैसा ही है जैसे कोई अपने ही घर की चीजें तोड़ दे और फिर अव्यवस्था का रोना रोए। सभ्यता की पहचान ऊंची इमारतों, भव्य आयोजनों या चमकदार ढांचों से नहीं होती। उसकी पहचान नागरिकों के छोटे-छोटे व्यवहार से होती है। संस्कार किसी योजना या बजट से नहीं आते, वे रोजमर्रा के आचरण से बनते हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रशासन ने कितनी सुरक्षा की या कितने गमले लगाए, सवाल यह है कि क्या हम ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जहां सार्वजनिक नैतिकता केवल भाषणों और उपदेशों तक सीमित रह गई है!

किसी भी सभ्यता का पतन अचानक नहीं होता। यह धीरे-धीरे होता है। शब्दों से पहले व्यवहार में, नीतियों से पहले आदतों में। जब नियम केवल दूसरों के लिए रह जाते हैं और सुविधा नैतिकता से बड़ी हो जाती है, तब पतन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है- चाहे बाहर से सब कुछ कितना ही आधुनिक क्यों न दिखे। ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास का अर्थ क्या केवल भव्य आयोजन, सजावट और चमकदार ढांचे हैं। अगर नागरिकों में जिम्मेदारी, संयम और साझा स्वामित्व का भाव नहीं होगा, तो यह विकास सतही और अल्पकालिक साबित होगा। नियमों का पालन डर से नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी से होना चाहिए, क्योंकि सभ्यता शोर से नहीं बचती, वह चुपचाप निभाए गए कर्तव्यों से बचती है। और इतिहास आखिर इन्हीं कर्तव्यों का हिसाब रखता है।

दुनिया मेरे आगे

> हम अक्सर उन देशों की प्रशंसा करते हैं, जहां सड़कें साफ हैं, सार्वजनिक व्यवस्था सुचारु है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह नागरिकों के छोटे-छोटे निर्णयों का फल है- कचरा जहां-तहां न फेंकने, नियम न तोड़ने और जो अपना नहीं है, उसे न छूने का निर्णय। सभ्यता इन्हीं निर्णयों से बनती है।

विरासत के जरिए गणित का पाठ पढ़ाएगा एनसीईआरटी

सुशील राघव

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आठवीं के विद्यार्थियों को भारतीय विरासत के माध्यम से गणित का पाठ पढ़ाएगा। परिषद ने हाल ही में आठवीं कक्षा के लिए गणित की दूसरी पुस्तक 'गणित प्रकाश' भाग दो जारी की है जिसमें भारतीय विरासत के कई उदाहरणों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं इस पुस्तक में विद्यार्थियों को समझाने के लिए रोजमर्रा के ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

पुस्तक की प्रस्तावना में कहा गया है कि अलग-अलग अवधारणा के लिए संदर्भ देते समय भारतीय विरासत का भी ध्यान रखा गया है। विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध गणितीय विरासत और गणित में इसके वैश्विक योगदान के बारे में जागरूक करने के लिए समस्या-समाधान दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में पुस्तक में भारतीय गणितज्ञों के योगदान को भी शामिल किया गया है। पुस्तक में पहला अध्याय 'भिन्न' के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि 'दशमलव भिन्न' शुरू होने से बहुत पहले, दसवें, बीसवें और सौवें हिस्से में गणना के लिए इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। 'प्रति सौ' का विचार ईसा पूर्व चौथी सदी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इस अध्याय में विद्यार्थियों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की गणना आदि के बारे में भी बताया गया है।

पुस्तक का दूसरा अध्याय 'बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय' पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि बौधायन, जो एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे (लगभग 800 ईसा पूर्व), इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रमेय को इस सामान्य रूप में और असल में आधुनिक रूप में बताया। उन्होंने सदियों पहले अपने 'शुल्बसूत्र' ग्रंथों में उस सिद्धांत का वर्णन किया। इस प्रमेय को ग्रीक दार्शनिक-गणितज्ञ पाइथागोरस (लगभग 500 ईसा पूर्व) के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस प्रमेय की तारीफ की और इसका अध्ययन भी किया। इसे अक्सर 'बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय' भी कहा जाता है ताकि सभी को पता चल सके कि किस प्रमेय की बात हो रही है। बौधायन ने बताया कि एक वर्ग का विकर्ण मूल वर्ग

आठवीं कक्षा की नई किताब में पैटर्न को समझने के लिए भारत के प्राचीन मंदिरों का उदाहरण लिया गया है। नई किताब में बौधायन-पाइथागोरस प्रमेय शामिल किया गया है। यह प्रमेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बौधायन (करीब 800 ईसा पूर्व) की देन है, जो पाइथागोरस से सदियों पहले था।

पहल

के क्षेत्रफल से दोगुने क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाता है। या समकोण त्रिभुज के लिए आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योग हमेशा विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बौधायन ने वेदियों के निर्माण के लिए व्यावहारिक ज्यामितीय अनुप्रयोग प्रदान किए, जिसमें समकोण त्रिभुजों के लिए प्रमेय भी शामिल है।

चौथा अध्याय ज्यामितीय विषयों को लेकर है। इसमें बताया गया है कि गणितीय आकृतियों (फ्रैक्टल्स) का इस्तेमाल इंसानों की बनाई कला में भी लंबे समय से होता आ रहा है। शायद सबसे पुरानी ऐसी गणितीय आकृति भारत के मंदिरों में मिलती है। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर में मिलता है, जो लगभग 1025 ईसवी में पूरा हुआ था। वहां एक ऊंची मंदिर की संरचना दिखती है जो पूरी संरचना की छोटी-छोटी प्रतिलिपियों से बनी है, जिस पर उसी संरचना की और भी छोटी प्रतिलिपि हैं और इसी तरह आगे भी। गणितीय आकृति जैसे पैटर्न मदुरै, हम्पी, रामेश्वरम, वाराणसी और कई अन्य मंदिरों में भी मिलते हैं। पुस्तक में अंतिम और सातवां अध्याय 'क्षेत्रफल' पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि 'शुल्बसूत्र' में हमें क्षेत्रफल के विषय पर कई दिलचस्प समस्याएं मिलती हैं। 'शुल्बसूत्र' वेदियों (धार्मिक मंच) के निर्माण से भी संबंधित है।

सूर्य घर योजना : नव वर्ष में सौर ऊर्जा से एक करोड़ घर रोशन होंगे

पंकज रोहिला

योजना में आसानी से उपभोक्ता को केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता की मदद मिल सके। इसके लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक सहायता से जोड़ दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

देश में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (पीएमएसजी) के तहत एक करोड़ घरों तक यह योजना पहुंचेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत आम जनता को सस्ती दरों पर सौर उपकरण उपलब्ध कराना है ताकि अधिक से अधिक कार्बन तत्व में कमी लाई जा सके। योजना में आसानी से उपभोक्ता को केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता की मदद मिल सके। इसके लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक सहायता से जोड़ दिया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

दो साल में इस तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय को कड़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि कुल एक करोड़ के लक्ष्य से अभी भी मंत्रालय साढ़े अस्सी लाख यूनिट के लक्ष्य से पीछे है। सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली दी जा रही है और इस योजना का लाभ लेकर उपभोक्ता अपना हर साल का बिजली बिल कम कर सकते हैं। इस योजना में तीन से पांच किलोवाट के उपकरण लगाए जाते हैं, जोकि एक परिवार की बिजली की खपत को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। एक रपट के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह तक कुल 19,45,758 घरों में सोलर उपकरण लगाए गए हैं। जिससे कुल 24,35,196 परिवारों को लाभ हुआ है। इस योजना जुड़े हैं और इन परिवारों का मासिक बिजली बिल शून्य दर्ज किया गया है।

योजना के तहत अब तक 13926 करोड़ रुपए की सहायता उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है और 8.3 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 75021 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। देश में करीब-करीब सभी राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है और नए प्रावधानों की मदद से योजना को और अधिक तेजी लागू किया जा सकेगा। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक के मुताबिक पीएमएसजी योजना एक मांग आधारित योजना है और देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय बिजली कंपनी (डिस्काम) से जुड़ा कनेक्शन है, वे इस योजना के तहत पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं।

लक्ष्य

नए प्रावधानों को आम जनता के लिए आसानी से इस योजना से जुड़ने के लिए किए गए हैं। सरकार इस योजना के लिए उपभोक्ता को राष्ट्रीय बैंकों से रेपो दर और वर्तमान में 5.76 प्रतिवर्ष के रियायती ब्याज दर पर दस वर्ष की अवधि के साथ फ्री लोन देती है। इस योजना के तहत आम जनता को अधिकतम 78 हजार रुपए की मदद की जाती है, जोकि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जाती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन की एक बिजली उत्पादन दर तय की है, जिसके आधार पर ही पहले आने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त योजना को तेजी से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए समय- समय पर योजना की समीक्षा भी मंत्रालय स्तर पर की जा रही है।

JANSATTA PAGE NO- 7

कई सवालों के जवाब देगा नया साल

राहुल वर्मा

भाजपा, कांग्रेस और वामदलों से लेकर कई क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए 2026 में राजनीतिक मोर्चे पर काफी कुछ दांव पर लगा है

देश के राजनीतिक परिदृश्य को निर्धारित करने के दृष्टिकोण से अगला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगले वर्ष बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें सभी दलों का कुछ न कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे धनाढ्य नगर निकाय बृहनमुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव भी होने हैं। कुछ राज्यसभा की रिक्त हो रही सीटों पर चुनाव की स्थिति में भी दलों के बीच खींचतान होती हुई दिख सकती है। अगला साल कई राजनीतिक पहेलियां भी सुलझाएगा। जैसे कि क्या देश भर में बड़े पैमाने पर विस्तार कर चुकी भाजपा अपने लिए राजनीतिक रूप से अनुर्वर साबित हो रहे प्रदेशों में भी अनुकूल स्थितियां बनाकर पैठ बढ़ा पाएगी या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद पटरी पर आई कांग्रेस की जो गाड़ी फिर से बेपटरी हुई, क्या वह वापस पटरी पर आ पाएगी या नहीं? क्या अस्तित्व के संकट से जूझ रहे वामदल अपनी सत्ता के आखिरी दुर्ग को बचा पाएंगे या नहीं? क्षेत्रीय दल किस नियति को प्राप्त होंगे?

भाजपा की चर्चा की जाए तो विधानसभा चुनाव इसकी पुष्टि करेंगे कि नए क्षेत्रों में पैठ बनाने के उसके प्रयासों को कितनी सफलता मिलेगी? जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहां केवल असम में ही उसकी सरकार है और पुडुचेरी में उसके समर्थन वाली सरकार सत्तारूढ़ है। दस साल से असम की सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए फिर से सत्ता में वापसी की ठीकठाक संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन यह तय है कि उसे इस बार गौरव गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। अगर कांग्रेस ने राजनीतिक कौशल दिखाया तो भाजपा के समीकरण गड़बड़ा भी सकते हैं। बंगाल में तमाम प्रयासों के बावजूद पार्टी दूसरे क्रम पर ही अटकी हुई है। ममता बनर्जी ने राज्य की सत्ता पर जिस मजबूती के साथ पकड़ बनाई हुई है, उससे भाजपा के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। हालांकि बिहार की जीत से उत्साहित भाजपा नई ऊर्जा के साथ बंगाल के रण में उतरने की तैयारी कर रही है। एक रणनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उसने जोर-शोर से उठाना शुरू कर दिया है।

दक्षिण में केरल और तमिलनाडु भाजपा के लिए दूर की कौड़ी बने हुए हैं। लोकसभा की 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भरसक कोशिशों के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में वह वहां गठबंधन सहयोगियों के ही भरोसे है। केरल की दो ध्रुवीय राजनीति में भाजपा फिलहाल तीसरा ध्रुव बनने पर ही ध्यान टिकाए हुए है। तिरुअनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत से उसे थोड़ी ही सही, लेकिन ताकत और हौसला जरूर मिला है। ऐसे में देखना यही होगा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी कितनी मजबूती से अपनी चुनौती पेश करती है?

कांग्रेस के लिए अगला साल कम चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला। असम में वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस बंगाल में तो लगभग हाशिए पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में वह द्रमुक की पिछलग्गू बनकर रह गई है। पार्टी की वास्तविक उम्मीदें केरल से जुड़ी हुई हैं, जहां वह वाम दलों के मोर्चे से सत्ता झटकने की व्यूह रचना बनाने में जुटी है। उसके लिए अनुकूल संकेत हैं कि हाल के निकाय चुनाव में पार्टी को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि अतीत के कई चुनावों में जीती हुई बाजी हारने के लिए जानी-जाने वाली कांग्रेस के लिए केरल में भी समस्याएं कम नहीं हैं। पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचतान की स्थिति है। स्थानीय इकाई में गुटबाजी के अलावा प्रदेश नेतृत्व को ताकतवर महासचिव केसी वेणुगोपाल को लेकर भी आशंकाएं कम नहीं हैं कि सत्ता मिलने पर वह मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। एक समय राज्य में पार्टी नेतृत्व को लेकर स्पष्टता का रुख रहा है, लेकिन एके एंटनी के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद से प्रदेश में नेतृत्व को लेकर स्वीकार्यता की स्थिति बनाने में संघर्ष ही करती रही है। इसे यदि समय से नहीं सुलझाया गया तो केरल की सत्ता का सिंहासन उससे दूर ही रह जाएगा।

वामदलों के लिए भी अगला साल अस्तित्व के सवाल से जुड़ा है। लंबे समय से बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता पर काबिज रहे वामदल अब इन दोनों राज्यों में राजनीतिक वनवास भोग रहे हैं। अगर केरल की सत्ता से भी उनकी विदाई होती है तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक ऐसे समय में जब यह विचारधारा भारत में अपने आगमन के सौ वर्षों का सफर पूरा कर चुकी है तो सत्ताशून्यता की ऐसी संभावित स्थिति उसकी वैचारिक प्रासंगिकता पर प्रश्न ही उठाएगी। कुछ अन्य क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए भी अगला साल बहुत कुछ निर्धारित करेगा। बंगाल में तृणमूल जिस जज्बे के साथ जुटी हुई है, उससे लगता नहीं कि वह प्रतिद्वंद्वी भाजपा को आसानी से राजनीतिक बढ़त बनाने की गुंजाइश देगी। हालांकि भाजपा जिस रणनीति और संसाधनों के साथ चुनाव लड़ती है उसे देखते हुए ममता बनर्जी के लिए भी राह आसान नहीं होगी। तमिलनाडु में द्रमुक का गढ़ कुछ अभेद्य लगता है, क्योंकि जयललिता के निधन के बाद राज्य में जो राजनीतिक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हुई, उसकी अभी तक भरपाई नहीं हो सकी। अन्नाद्रमुक में आंतरिक खींचतान ने भी मुख्यमंत्री स्टालिन का काम आसान ही किया है। हालांकि इतने वर्षों के सत्ता विरोधी रुझान और भाजपा के समन्वित प्रयासों से विपक्षी गठबंधन में नई ऊर्जा स्टालिन के लिए चुनौती बढ़ाने का काम जरूर करेगी। अभिनेता से नेता के रूप में स्थापित होने के प्रयासों में जुटे विजय की पार्टी भी कुछ सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। एक लंबे समय के बाद साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ मिलकर भी सफलता हासिल नहीं कर पाए तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य अधर में अटक जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी चुनाव से पहले मेल-मिलाप जारी है लेकिन उससे हासिल क्या होगा? अगला साल ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर आएगा।

(लेखक चेन्नई स्थित शिव नादर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली में फेलो हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

DAINIK JAGARAN PAGE NO- 10

संघर्ष, सामंजस्य और प्रगति

कभी आप इस प्रश्न से गुजरे हैं कि प्रगति का मूल आधार क्या है? जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति संघर्ष और सामंजस्य के माध्यम से ही संभव होती है। जहां संघर्ष नहीं, वहां गति नहीं और जहां सामंजस्य नहीं, वहां स्थायित्व नहीं। ऐसी प्रगति में स्वयं आंदोलन ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। जीवन ठहराव को स्वीकार नहीं करता, वह निरंतर रूपांतरण चाहता है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया को एक सूक्ष्म दार्शनिक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जब किसी कला या क्षमता के विकास की संभावनाएं सिमटने लगती हैं और वह अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तब उसे 'पराकाष्ठा' कहा जाता है। उस अवस्था में आगे कोई परिवर्तन संभव नहीं रहता और गति एक सीधी रेखा में चलने लगती है। एक पापी के संदर्भ में इसे पाप की पराकाष्ठा कहा जाएगा, जबकि आध्यात्मिक साधक के जीवन में यह लक्ष्य की ओर अंतिम गहन गति का संकेत है।

मनुष्य स्वभावतः लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला प्राणी है। लक्ष्य के अभाव में किया गया सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसे समझने के लिए नाव का उदाहरण अत्यंत सारगर्भित है। यदि कोई नाव चला रहा हो, पर उसे यह ज्ञात न हो कि नाव को कहां ले जाना है, तो उसका समस्त प्रयास निष्फल सिद्ध होगा। जब नाव को धारा के सहारे छोड़ दिया जाता है, तो वह गहरे समुद्र की ओर बह जाती है और किनारे की दृष्टि खो देती है। इसमें श्रम नहीं लगता, पर दिशा का अभाव होता है। इसके विपरीत, यदि नाव को बिना उपयुक्त साधन के ऊपर की ओर खींचा जाए, तो यह केवल मांसपेशियों का अनावश्यक खिंचाव बन जाता है, जिसका दीर्घकालिक कोई लाभ नहीं।

सर्वोत्तम स्थिति यही है कि पाल ठीक से लगाए जाएं और हवा के साथ सामंजस्य बनाकर नाव को आगे बढ़ाया जाए। इस अवस्था में नाव सहज रूप से चलती है। इसी सहज प्रवाह में जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें 'भटियाली' कहा जाता है। इसमें श्रम नहीं, बल्कि अवकाश और लय होती है। नाविक के पास स्वर को लंबा खींचने, भाव में डूबने और गीत को विस्तार देने का समय होता है। इसके विपरीत, जब नाव धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाती है, तब नाविक को तीव्र संघर्ष करना पड़ता है। उस समय गाए जाने वाले गीत 'उजानिया' कहलाते हैं। इनमें स्वर छोटा, तीखा और संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि नाविक के पास विश्राम या विस्तार का अवसर नहीं होता। यह गीत श्रम, संघर्ष व प्रतिरोध की ध्वनि है।

> **जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति, हरेक स्पंदन किसी न किसी रूप में पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। संघर्ष और सामंजस्य, अंधकार और प्रकाश, श्रम और सहजता, यही जीवन की गति है।**

इस प्रकार, जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति, प्रत्येक स्पंदन, किसी न किसी रूप में पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। संघर्ष और सामंजस्य, अंधकार और प्रकाश, श्रम और सहजता, यही जीवन की गति है और इसी गति में प्रगति का वास्तविक अर्थ निहित है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

HINDUSTAN PAGE N0- 16

लापरवाही बढ़ा रही सड़क हादसों को

देश में हर दिन कोई न कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होती है। कभी-कभी तो एक ही दिन कई जानलेवा हादसे होते हैं, जिनमें कई लोग मारे जाते हैं। इधर घने कोहरे के कारण मार्ग दुर्घटनाओं का जोखिम और बढ़ गया है। पिछले दिनों घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कई मार्ग दुर्घटनाएं हुईं। इनमें सबसे भयंकर रही आगरा से नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर। यहां एक कार और बस की टक्कर होने के बाद एक के बाद एक कुल 11 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिनमें छह स्लीपर कोच और दो रोडवेज बसें भी थीं। टक्कर के बाद कई वाहनों में आग लग गई, जिसमें दर्जन भर लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनकी पहचान मुश्किल हो गई। एंबुलेंस, पुलिस, फायर सर्विस अथवा परिवहन से संबंधित कोई इकाई उनकी मदद नहीं कर सकी। डीएनए टेस्ट द्वारा उनके संबंधियों से मिलान कर शवों की पहचान की गई। उन परिवारों की पीड़ा का बयान शब्दों में संभव नहीं। ऐसी हर दुर्घटना के पीछे लापरवाही होती है।

जब रात्रि के घने कोहरे में पैदल यात्रियों को भी चलना दूभर हो जाता है, तब पूरी रफ्तार से बिना आवश्यक सावधानी के स्लीपर या रोडवेज बसों का चलना गंभीर अपराध कहा जाएगा। यदि चालक अत्यधिक ड्यूटी के कारण नींद की झपकी ले रहे थे या वाहनों में आवश्यक फाग लाइटें नहीं थीं, अथवा कोई अन्य तकनीकी कमी थी तो यह बस मालिकों की भी गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। पूरा देश जानता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रतिवर्ष पूरे उत्तर भारत में कोहरा पड़ता है, जो अचानक किसी दिन घने, किसी दिन बहुत घने और कभी बहुत हल्का होता है। आगरा-नोएडा एक्सप्रेसवे पर जिस दिन दुर्घटना हुई, उसके दो दिन पूर्व घने कोहरे के कारण लखनऊ इकाना स्टेडियम में होने वाला क्रिकेट मैच खिलाड़ियों के मैदान में उतर जाने के बाद भी स्थगित करना पड़ा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी कोहरे को लेकर थी, परंतु इन गाड़ियों की रफ्तार नियंत्रण और चेकिंग इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कम से कम कुछ चेकपोस्टों पर लाउडस्पीकरों से घोषणा कर वाहन चालकों को आगाह किया जा सकता था,

यशपाल सिंह

सड़क सुरक्षा भविष्य में बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या होने वाली है। इसका समय से सही समाधान अनिवार्य है

चिंतित करती सड़क हादसों की संख्या ● फाइल

लेकिन किसी को चिंता नहीं थी। प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका मूल कारण किसी उच्चतम अधिकारी की स्पष्ट जिम्मेदारी का न होना है। इसका कारण यह है कि किसी की जवाबदेही नहीं होती और न ही कोई चिंता करता है। परिवहन विभाग ट्रैफिक पुलिस पर और ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग पर दोष डालकर शांत हो जाते हैं और कुछ दिन बाद घटना भुला दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी अब चौराहों तक सीमित है, ताकि यातायात अबाध रूप से चलता रहे।

आगरा-एक्सप्रेसवे पर भयंकर दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रुख अपनाते ही दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सक्रिय हो गया। आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 50 पायलट गाड़ियां तैनात कर दी गईं और 75 संवेदनशील स्थान भी चुन लिए गए, जहां से गाड़ियां काफिले में नियंत्रित गति से चलाना प्रारंभ की गई। चिह्नित स्थानों पर ब्लिंकर्स लगाए गए। जगह-जगह लाउडस्पीकर लगाकर सतर्क करने की व्यवस्था की गई। इन चारों एक्सप्रेसवे पर हर 50 किमी की दूरी पर विशेष वाहनों की तैनाती की गई, जिसमें गश्ती वाहन, एंबुलेंस और रेस्क्यू वाहन लगाए गए। गाड़ियों को प्रवेश बिंदुओं पर रोककर रिफ्लेक्टर और फाग लाइटें लगाई गईं। अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की गई। वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर उसे लागू किया गया और न मानने वालों के चालान काटे गए। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यह सब पहले नहीं किया जा सका। पुलिस और प्रशासन दुर्घटना होने के बाद चेतता है। इसका एक कारण यह है कि देश भर में आम तौर पर यातायात पुलिस को शहर के चौराहों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में पुलिस से अधिक प्रभावशाली योगदान किसी और विभाग का हो ही नहीं सकता।

सभी प्रदेशों में थानों-चौकियों के जरिये हर कहीं यातायात पुलिस की पहुंच है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी को उपलब्ध रहती है और किसी भी घटना स्थल पर सबसे पहले वही पहुंचती है। पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 दुर्घटनाएं होती हैं। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उनके प्रति अफसोस प्रकट कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। कभी-कभी लगता है कि वाहन चालकों को कानून का कोई भय ही नहीं है। इस व्यवस्था में सुधार तब तक संभव नहीं है, जब तक कि एक विभाग विशेष की जवाबदेही तय नहीं कर दी जाती। जिम्मेदारी जवाबदेही से आती है। यही विभाग अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर पूरे वर्ष बदलते मौसम, त्योहारों, विशेष यात्राओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हो।

अपने देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो देश के विकास के साथ-साथ भविष्य में दोगुनी गति से बढ़ेगी। लिहाजा यातायात पर विशेष ध्यान देते हुए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए और शानदार हाईवे भी बनाए जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा भविष्य में बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्या होने वाली है। इसका समय से सही समाधान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं)

response@jagran.com

DAINIK JAGARAN PAGE NO- 10

इस साल के जख्म ताउम्र सालते रहेंगे

गुजर रहा वर्ष 2025 भारत के इतिहास में केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि स्मृतियों में दर्ज उन जख्मों को छोड़ गया है, जो समय के साथ भी आसानी से भरने वाले नहीं हैं। इस साल आतंक, तकनीकी विफलताओं, भीड़ प्रबंधन की चूक और सुरक्षा में सेंध से जुड़ी घटनाओं ने पूरे राष्ट्र को भीतर तक झकझोर दिया। कश्मीर की शांत वादियों में पहलगाम की बैसरन घाटी में धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने मानवता को शर्मसार किया और यह एहसास कराया कि आतंकवाद का जहर अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि, 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिये भारत ने यह संदेश भी दिया कि वह चुप बैठने वाला नहीं है। राजधानी दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुआ कार धमाका यह बताने के लिए काफी था कि खतरे केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि राजधानी तक हैं, जहां पढ़े-लिखे और प्रतिष्ठित पेशे भी हिंसा के सूत्रधार बन सकते हैं।

बेंगलुरु में आईपीएल जीत का उत्सव जिस तरह मातम में बदला, उसने साबित कर दिया कि खुशियों के क्षण भी अव्यवस्था और लापरवाही के कारण त्रासदी बन सकते हैं, वहीं अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा तकनीकी उत्कृष्टता के दौर में मानवीय और प्रणालीगत चूक की भयावह कीमत को सामने ले आया। प्रयागराज महाकुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ों ने यह कड़वा सच उजागर किया कि आस्था, यात्रा व उत्सव के आयोजनों में प्रबंधन का अभाव सीधे जानलेवा बन जाता है। इन सभी घटनाओं ने अलग-अलग रूप में एक ही सवाल खड़ा किया कि क्या हम केवल प्रतिक्रिया देने वाला समाज बनकर रह गए हैं या समय रहते उससे सीख लेकर भविष्य को सुरक्षित बनाने की इच्छाशक्ति भी रखते हैं? इन त्रासदियों ने हमें यह सिखाया कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, संवेदनशील शासन, जवाबदेह व्यवस्था, पारदर्शिता व मानवीय करुणा से मजबूत होती है।

बहरहाल, अब जब नया वर्ष दस्तक दे रहा है, तब यह केवल नई तारीख नहीं, बल्कि नई सोच, नई प्रतिबद्धता और नई दिशा का अवसर है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला वर्ष भारत के हर नागरिक के जीवन में आशा का दीप जलाए, कोई भूखा न सोए, हर व्यक्ति को सुलभ व सम्मानजनक चिकित्सा-सुविधा मिले और विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। देश की प्रगति केवल ऊंची इमारतों और आंकड़ों से नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन, सामाजिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों से मापी जाए। नया वर्ष में भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बने, बल्कि करुणा, सुरक्षा और शांति की वैश्विक मिसाल बने, यही कामना है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

अलविदा 2025

2025 उपलब्धियों का वर्ष साबित हुआ

यह सही है कि हम नकारात्मक घटनाओं के कारण ही किसी वर्ष को याद रखते हैं, लेकिन साल 2025 में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हमने हासिल कीं, जो उन घटनाओं पर भारी साबित हुई हैं। इसीलिए, मेरी नजर में यह उपलब्धियों का वर्ष है। फिर चाहे वह खेल के क्षेत्र हो, विज्ञान हो, वैश्विक मंचों को प्रभावित करना हो या फिर शासन में देशवासियों की भागीदारी बढ़ाना, तमाम मोर्चों पर देश आगे बढ़ा है।

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि भारत ने सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इसी साल 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे सैन्य अभियान चलाए गए, जो संकेत थे कि भारत अपनी सुरक्षा से किसी किस्म का समझौता न करना सीख लिया है और अब दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देने की हिम्मत पैदा कर ली है। इसी तरह, 'वंदे मातरम' का यह 150वां वर्ष था, जिसके लिए केंद्र सरकार ने खास तरह के अभियान चलाए। उनमें देशवासियों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई और 2047 तक देश को विकसित बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। खेल की बात करें, तो इस साल पुरुष और महिला, दोनों क्रिकेट टीमों ने आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा किया। पुरुष क्रिकेट टीम ने जहां चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। 'ब्लाइंड ट्वेंटी-20' विश्व कप भी महिला खिलाड़ियों ने जीता और इतिहास रच दिया। एशिया कप में भी तिरंगा लहराया।

अंतरिक्ष, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी इस साल काफी काम हुए। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने, जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे। इसरो न सिर्फ स्वदेशी, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष भेजने लगा है। पिछले दिनों 'बाहुबली', यानी सबसे भारी सैटेलाइट का भी प्रक्षेपण किया गया। इसी तरह, पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से देखें, तो भारतीय रेलवे अपने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को पूरा करने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। अब अपना देश जीवाश्म ईंधन से हटकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

हालांकि, इस साल प्रयागराज महाकुंभ में दुखद हादसा हुआ, लेकिन महाकुंभ, अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण जैसे आयोजनों ने भारत की आस्था, संस्कृति व विरासत को आगे बढ़ाने का ही काम किया। ऐसे आयोजनों ने भारतीयों में न सिर्फ उत्साह पैदा किया, बल्कि उनको आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित भी किया। इसी कारण 2026 को लेकर तमाम उम्मीदें जताई जा रही हैं। जाहिर है, नए साल में भारत नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगा।

रियांशी मिश्रा, टिप्पणीकार

HINDUSTAN PAGE NO- 16